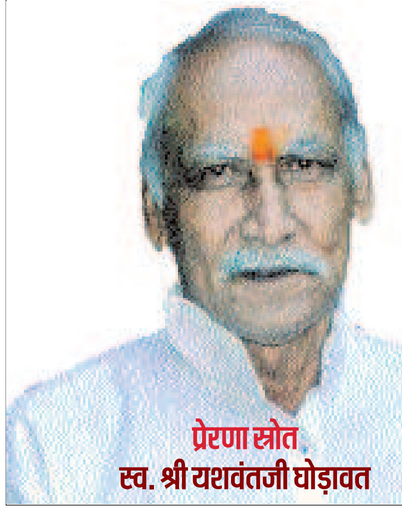

प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

माही की गूंज

बेबाकी के साथ..सच

www.mahikihunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-08, अंक -34 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरुवार 11 जून 2026 | पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सुविचार

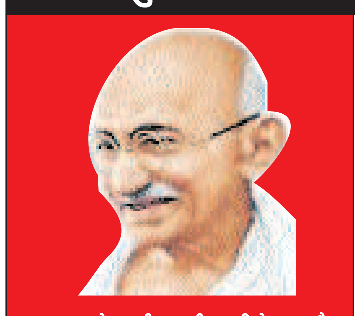

कमजोर कभी क्षमाशील नहीं हो सकता है, क्षमाशीलता ताकतवर की निशानी होती है...
◀◀ महात्मा गांधी

बचत उत्सव समाप्त

अच्छे दिन जाने वाले हैं...?

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

मनुष्य भी अजीब प्राणी है अच्छे समय की तलाश में पूरा जीवन निकाल देता है और बाद में पता चलता है कि, जो बीत चुका वही अच्छा समय था। 2014 के चुनाओ में भाजपा ने नारा दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं और ऐतिहासिक बहुमत के साथ भाजपा ने सरकार बनाई। अब सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने का जश्न मना रही है, वहीं आम जनता को अभी तक अच्छे दिनों की तलाश है। देश भर में जश्न के माहौल के बीच आम जनता के मन में एक ही प्रश्न है अच्छे दिन कब आएंगे...? वैसे तो अच्छे दिनों की कोई परिभाषा नहीं है और एक व्यक्ति के लिए अच्छा दिन होना सभी पर लागू नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी सरकार का प्रयास है कि, आम जनता के लिए अच्छे दिन आए। वही आम जनता को लगता है कि, आम जनता का तो पता नहीं लेकिन सरकार के लिए अच्छे दिन अवश्य आ चुके हैं।

सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती करते हुए बचत उत्सव मनाने की घोषणा की थी और बचत उत्सव का जोर-शोर से प्रचार किया था लेकिन वह बचत उत्सव ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। अमेरिका-ईरान की जंग शुरू होने के बाद क्रूड ऑयल तेल में तेजी आने से पेट्रोल और डीजल भी महंगा हुआ और महंगे पेट्रोल-डीजल का असर सीधे जनता की जेब पर पड़ा। और सरकार द्वारा घोषित बचत उत्सव वाले सस्ते दिन ज्यादा टिक नहीं पाए। जीएसटी में कटौती की घोषणा में सरकार की निगरानी सूची में शामिल 54 वस्तुओं में 41 वस्तुओं के दाम अब 22 सितंबर 2025 को हुई जीएसटी कटौती से पहले के दामों से भी ज्यादा महंगी हो चुकी है। 28 फरवरी 2026 से शुरू हुई अमेरिका-ईरान जंग के बाद कच्चे तेल की कीमत तेजी से बड़ी जिससे पेट्रोल और डीजल के दामों में भी वृद्धि की गई और सामान की लागत भी बढ़ गई। जिससे वस्तुओं के दाम जीएसटी दरों में कटौती के बावजूद पहले से ज्यादा बढ़ गए। यानी बचत उत्सव समाप्त होकर जनता की जेब पर पहले से ज्यादा बोझ बढ गया। जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ा है।

आगे क्या...?

कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि, किसी भी युद्ध का असर केवल तात्कालिक नहीं होता है बल्कि दीर्घकालीन रहता है और युद्ध का परिणाम केवल लड़ने वाले देशों पर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। मध्य पूर्व का संघर्ष केवल तेल की कीमत ही नहीं बढ़ाता है बल्कि आम जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियों पर भी पड़ता है। अगर युद्ध आज भी समाप्त हो जाए तो भी उसका असर लंबे तक समय रहना निश्चित है।

पूर्व न्यायाधीश को मिली धमकियों पर मुख्य न्यायाधीश सख्त

नई दिल्ली, एजेंसी।

बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस गौतम पटेल को उनके एक न्यायिक निर्णय के संबंध में मिल रही धमकियों के मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। इस मुद्दे पर देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने संज्ञान लेते हुए जस्टिस पटेल और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की है।

जानकारी के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने अपने आधिकारिक ब्रिटेन दौरे के दौरान लंदन स्थित भारतीय उच्चायुक्त के समक्ष यह मामला उठाया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की। मामला सामने आने के बाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त पी. कुमारन से संपर्क किया। भारतीय उच्चायोग ने जस्टिस पटेल और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है। साथ ही लंदन पुलिस द्वारा भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने की जानकारी दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को भी इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच बार एसोसिएशन ऑफइंडिया ने जस्टिस पटेल को दी जा रही धमकियों की कड़ी निंदा की है। संगठन ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन पर सीधा हमला बताया है। एसोसिएशन ने कहा कि किसी न्यायाधीश पर दबाव बनाकर अथवा धमकाकर न्यायिक निर्णय बदलवाने का प्रयास लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। संगठन ने भारत और ब्रिटेन की जांच एजेंसियों से दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि, जस्टिस गौतम पटेल ने हाल ही में खुलासा किया था कि उन्हें वर्ष 2024 में दाऊदी बोहरा समुदाय से जुड़े एक ऐतिहासिक निर्णय के कारण धमकी भरे संदेश और पत्र प्राप्त हो रहे हैं। अपने निर्णय में उन्होंने सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को दाऊदी बोहरा समुदाय का 53वां आध्यात्मिक गुरु घोषित किया था। इस निर्णय के विरुद्ध अपील अभी लंबित है।

पूर्व न्यायाधीश के अनुसार, धमकी देने वाले लोग उन पर सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करने का दबाव बना रहे हैं कि, उनका निर्णय गलत था। इसके लिए उनसे यूट्यूब पर वीडियो जारी करने की मांग भी की गई है। जस्टिस पटेल का कहना है कि, मुंबई में सीधे कार्रवाई संभव न होने के कारण उनकी लंदन में रहने वाली बेटी को निशाना बनाया जा रहा है। इस घटनाक्रम ने न्यायाधीशों की सुरक्षा तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर नई बहस छेड़ दी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ा पंडित नेहरू का रिकॉर्ड

नई दिल्ली, एजेंसी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश की राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया है। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मोदी अब स्वतंत्र भारत में निर्वाचित होकर सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले नेता बन गए हैं। पंडित नेहरू चुनाव जीतकर 4,398 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे थे, जबकि नरेंद्र मोदी ने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल का 4,399वां दिन पूरा कर यह उपलब्धि अपने नाम कर ली है। इस उपलब्धि और मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों में उत्साह का वातावरण है। सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की एक महत्वपूर्ण

बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सहित गठबंधन के सभी प्रमुख सहयोगी दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। बैठक में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विभिन्न क्षेत्रीय दलों के अध्यक्ष तथा गठबंधन के प्रमुख नेता शामिल हुए। बैठक में गठबंधन के 35 सहयोगी दलों के लगभग 75 वरिष्ठ नेताओं ने भागीदारी की। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जे.पी. नड्डा तथा शिवराज सिंह चौहान सहित कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त गठबंधन के घटक दलों से केंद्रीय मंत्री के. राम मोहन नायडू, राजीव रंजन सिंह, एच.डी. कुमारस्वामी तथा अनुप्रिया पटेल भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में आगामी राजनीतिक रणनीति, संगठनात्मक विषयों तथा विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके साथ ही नागरिकों के जीवन को अधिक सुगम बनाने तथा व्यापारिक गतिविधियों में सुविधा बढ़ाने संबंधी विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ। वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों तथा बड़े आधारभूत संरचना परियोजनाओं की समीक्षा भी बैठक के प्रमुख विषयों में शामिल रही। विशेष रूप से उन राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया जहां केंद्र और राज्य में एक ही गठबंधन की सरकारें कार्यरत हैं, ताकि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से कहा था कि सरकार भले ही वर्ष 2014 से सत्ता में है, लेकिन वर्ष 2026 में पूरा ध्यान भविष्य के लक्ष्यों तथा जनकल्याण पर केंद्रित रहना चाहिए।

सब्सिडी में कटौती : कांग्रेस का केंद्र सरकार पर निशाना

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रियायती रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या में कमी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महिला कल्याण और गरीबी उन्मूलन के बड़े दावे करती है, लेकिन व्यवहार में गरीब परिवारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की अनदेखी कर रही है।

मंगलवार को जारी बयान में खड़गे ने कहा कि सरकार लगातार जनकल्याणकारी योजनाओं में कटौती कर रही है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2016 में उज्ज्वला योजना प्रारंभ होने के समय प्रति वर्ष 12 रियायती रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया गया था। बाद में यह संख्या घटाकर 9 कर दी गई और अब इसे केवल 4 वार्षिक रिफिल तक सीमित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं से किए गए वादे के विपरीत है। खड़गे ने आरोप लगाया कि रसोई गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण लाखों लाभार्थियों के लिए सिलेंडर भरवाना कठिन होता जा रहा है। उनके अनुसार आर्थिक दबाव के चलते अनेक परिवार पुनः पारंपरिक चूल्हों और लकड़ी जैसे ईंधनों का उपयोग करने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होने का दावा करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर मिलने वाली राहत लगातार कम की जा रही है। कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि के बाद सामने आई है। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 913 रुपये से बढ़कर 942 रुपये हो गई है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रारंभिक चार रिफिल पर प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिसके बाद उन्हें प्रभावी रूप से 642 रुपये प्रति सिलेंडर का भुगतान करना होगा।

रसोई गैस पर केंद्र का दावा, उपभोक्ताओं को सालाना 8 हजार 4 सौ रुपए की बचत

नई दिल्ली।

घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में हाल ही में 29 रुपये की वृद्धि के बाद केंद्र सरकार ने दावा किया है कि उपभोक्ताओं को अब भी पर्याप्त राहत मिल रही है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की वास्तविक लागत 1,600 रुपये से अधिक है, जबकि इसे उपभोक्ताओं को 942 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार प्रत्येक सिलेंडर पर उपभोक्ताओं को लगभग 700 रुपये की अप्रत्यक्ष राहत मिल रही है। इस आधार पर यदि कोई परिवार वर्षभर में 12 सिलेंडर का उपयोग करता है तो उसे लगभग 8,400 रुपये की वार्षिक बचत होती है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रवीण खनूजा ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 300 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जा रही है। इस प्रकार उन्हें प्रति सिलेंडर लगभग 1,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, जो वर्ष में 12 सिलेंडरों के उपयोग पर 12,000 रुपये तक पहुंच सकता है।

हालांकि, रसोई गैस की कीमतों में हुई वृद्धि का सीधा प्रभाव घरेलू बजट पर भी पड़ रहा है। यदि कोई परिवार जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 तक प्रत्येक माह एक सिलेंडर का उपयोग करता है, तो मार्च और जून में हुई मूल्य वृद्धि के कारण उसे अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ा है। अनुमान के अनुसार यदि वर्ष के शेष महीनों में कीमतें स्थिर रहती हैं, तो आम उपभोक्ता पर इस वर्ष लगभग 803 रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक चुनौतीपूर्ण बताई जा रही है। उन्हें एक ओर बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सब्सिडी के दायरे में कमी का असर भी महसूस करना पड़ रहा है। पहले नौ सिलेंडरों पर कुल 2,700 रुपये की सब्सिडी उपलब्ध थी, जबकि अब यह सुविधा केवल चार रिफिल तक सीमित होकर 1,200 रुपये रह गई है। इस कारण लाभार्थियों को लगभग 1,500 रुपये की सब्सिडी का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

यदि कोई उज्ज्वला लाभार्थी वर्ष में 12 सिलेंडरों का उपयोग करता है, तो बढ़ी हुई कीमतों के कारण 803 रुपए तथा सब्सिडी में कमी के कारण 1,500 रुपये का अतिरिक्त भार पड़ सकता है। इस प्रकार कुल अतिरिक्त बोझ लगभग 2,303 रुपये वार्षिक तक पहुंच सकता है।

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रति सिलेंडर 300 रुपये की सब्सिडी केवल वर्ष के पहले चार रिफिल तक सीमित है, क्योंकि मंत्रालय के अनुसार औसतन उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवार वर्ष में चार से पांच सिलेंडर ही उपयोग करते हैं। मंत्रालय ने हालिया 29 रुपये की वृद्धि को भी सीमित प्रभाव वाली बताते हुए इसे प्रतिदिन लगभग एक रुपये के अतिरिक्त खर्च के बराबर बताया है।

भाजपा संगठन और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बदलाव की चर्चाएं तेज

नई दिल्ली।

भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक ढांचे तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद में संभावित बदलावों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में नई टीम की घोषणा शीघ्र हो सकती है। साथ ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद में भी कुछ नए चेहरों को शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 15 जून के बाद कभी भी नए पदाधिकारियों के नामों की घोषणा हो सकती है।

जनवरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद 45 वर्षीय नितिन नवीन संगठन में बदलावों को लेकर लगातार सक्रिय हैं। पार्टी की परंपरा के अनुसार नए अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने के बाद संगठनात्मक स्तर पर परिवर्तन किए जाते हैं। पार्टी नेतृत्व संगठन को अधिक युवा, अनुभवी तथा सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला स्वरूप देने पर विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि नई टीम में युवा और अनुभवी नेताओं का संतुलित समावेश देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति सहित विभिन्न सामाजिक वर्गों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने पर जोर रहेगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इन दिनों विभिन्न राज्यों का दौरा कर संगठन की स्थिति का आकलन कर रहे हैं। उनके द्वारा जुटाए जा रहे जमीनी फीडबैक को संगठनात्मक बदलावों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संभावित विस्तार और फेरबदल को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने के साथ ही मंत्रिपरिषद में बदलाव की संभावनाओं पर चर्चा बढ़ी है। हाल के घटनाक्रमों में केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा को क्रमशः उत्तर प्रदेश और दिल्ली में पार्टी की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद कुछ नए समीकरण बनने की संभावना व्यक्त की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार आगामी विधानसभा चुनावों और विभिन्न राज्यों में संगठन को मजबूत करने की रणनीति के तहत कई नेताओं को नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा दक्षिण भारत के राज्यों पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ तथा राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उनके भविष्य की भूमिका को लेकर भी चर्चा है। वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं को भी संभावित मंत्रिपरिषद विस्तार में प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना जताई जा रही है।

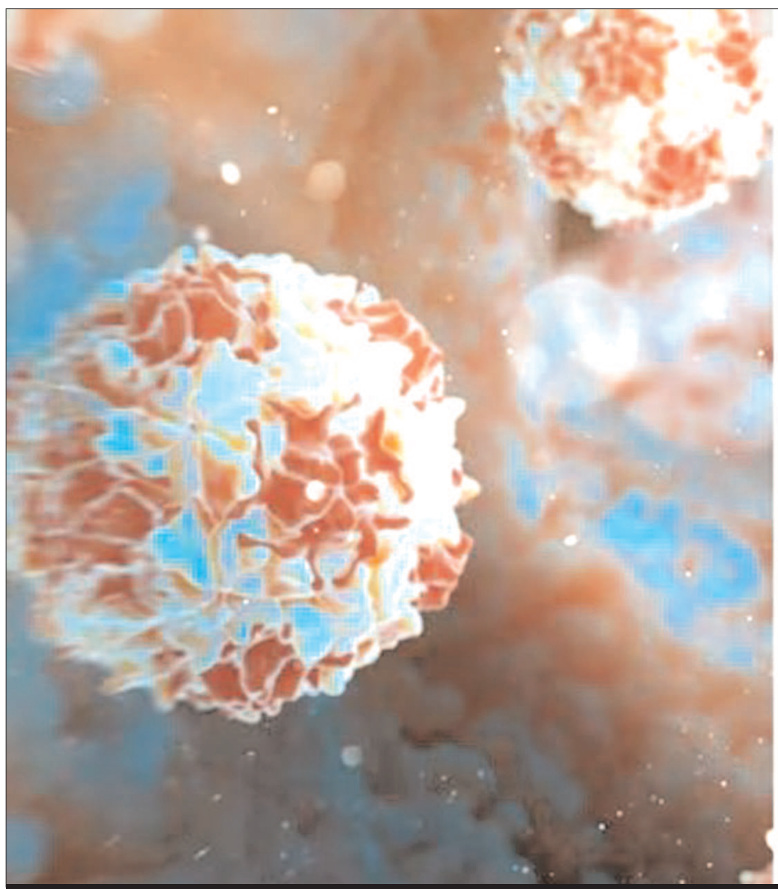

गाजियाबाद के सीवेज शोधन संयंत्र में पोलियो वायरस की पुष्टि

गाजियाबाद।

गाजियाबाद के डूंडाहेड़ा स्थित सीवेज शोधन संयंत्र से लिए गए दूषित जल के नमूने में वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियो वायरस (टाइप-1) की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी और स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पोलियो वायरस की नियमित निगरानी के तहत प्रत्येक माह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सीवेज शोधन संयंत्रों से नमूने एकत्र कर जांच के लिए भेजे जाते हैं। इसी क्रम में डूंडाहेड़ा स्थित संयंत्र से लिया गया नमूना दिल्ली की प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा गया था। हाल ही में प्राप्त जांच रिपोर्ट में वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियो वायरस टाइप-1 की उपस्थिति पाई गई।

रिपोर्ट सामने आने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में आपात बैठक आयोजित की गई, जिसमें वायरस की उत्पत्ति तथा नियंत्रण उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रभावित क्षेत्रों में विशेष सर्वे अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत 107 स्वास्थ्य टीमों को तैनात किया गया है।

ये टीमें घर-घर जाकर शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करेंगी तथा आवश्यकतानुसार पोलियो रोधी दवा पिलाएंगी। अभियान के तहत राजनगर, शास्त्रीनगर, बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र, दौलतपुरा, न्यू पंचवटी, घुकना, हिंडन विहार, कैला भट्टा, मिर्जापुर, विजय नगर तथा खैराती नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन-व्युत्पन्न पोलियो वायरस उन बच्चों में फैलने की आशंका अधिक रहती है जिनका पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है। स्वच्छता की कमी वाले क्षेत्रों में संक्रमित व्यक्ति के मल के माध्यम से यह वायरस सीवेज प्रणाली तक पहुंच सकता है और वहां से इसके प्रसार की संभावना बढ़ जाती है।

चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार यह वायरस कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले अथवा अपूर्ण टीकाकरण वाले बच्चों में गंभीर प्रभाव डाल सकता है। ऐसे मामलों में समय पर पहचान और रोकथाम अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी बढ़ाते हुए सभी संवेदनशील बच्चों की जांच और टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

जिला निगरानी अधिकारी ने बताया कि नियमित जांच के दौरान इस प्रकार वायरस की उपस्थिति मिलना गंभीर विषय है। विभाग ने मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जांच और नियंत्रण संबंधी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। साथ ही वायरस के स्रोत का पता लगाने और इसके संभावित प्रसार को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर निगरानी अभियान चलाया जा रहा है।

के.एफ रुस्तमजी अवार्ड से सम्मानित किए जाएंगे निरीक्षक कमलेश सिंगार

माही की गूंज, भामल।

झाबुआ जिले के छोटे से गांव भामल से निकले और देश भक्ति व जनसेवा को सरोकार करते हुए आगे बड़े। जो प्रदेश मे भी नाम रोशन कर रहे है। पुलिस विभाग मे पदस्थ थाना निरक्षक (टी,आई) कमलेश सिंगार जिनका भोपाल मे रुस्तम आवर्ड से समानित किया जाएगा। मध्यप्रदेश ग्रह विभाग द्वारा मध्यप्रदेश पुलिस के.एफ रुस्तम जी अवार्ड 2024 के लिए निरीक्षक कमलेश सिंगार का चयन हुआ है जिनका सम्मान आगामी समय में होना है। निरीक्षक सिंगार पूर्व में मन्दसौर-नीमच, तथा धार जिले में पदस्थ रहकर अपनी सेवाएं दे चुके है। तथा उनकी कार्यशैली को आज भी सराहा जाता है। पुलिस विभाग में निरीक्षक सिंगार द्वारा विभाग में सराहनीय कार्य करते हुए धार जिले के टांडा थाना प्रभारी रहते हत्या ,लूट ,डकैती जैसी जघन्य अपराध में लिप्त 48 कुख्यात बदमाशो को पकड़ने मे सफ्लता हासिल की। तथा आमर्स एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 100 से अधिक हथियारों की जब्ती भी की थी। तथा मन्दसौर में पदस्थ रहते हुए नाबालिक बालिका के साथ हुए दरिंदगी की घटना में आरोपियों को पकड़ने पर मुख्यमंत्री से सम्मानित भी किए गए थे। उत्कृष्ट पुलिसिंग, प्रभावी नेतृत्व, अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था के बेहतर संचालन एवं अच्छी कार्यशैली के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया जाएगा।

इस पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 की नकद राशि एवं प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा। यह सम्मान न केवल टि,आई, कमलेश सिंगार की कर्तव्यनिष्ठा और उत्कृष्ट सेवाओं का प्रमाण है, बल्कि पुरे पुलिस परिवार के लिए भी गौरव का विषय है।

निरीक्षक सिंगार वर्तमान में उज्जैन जिले के बड़नगर थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ है। उन्हें उज्वल भविष्य को लेकर परिवार इष्ट मित्रो ने बधाई दीं एवं उज्वल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित की।

देवी वैष्णवी के द्वारा श्रीमद्भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ हुआ संपन्न

माही की गूंज, पेटलावद।

श्री जी पथ भक्त मंडल द्वारा योग नगरी ऋषिकेश में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह के साथ सफ्लतापूर्वक संपन्न हुआ। गंगा तट पर आयोजित इस आयोजन में कथा प्रवक्ता देवी वैष्णवी जी भट्ट निवासी पेटलावद ने सात दिनों तक श्रीमद्भागवत महापुराण का रसपूर्ण वाचन करते हुए भगवान की विभिन्न लीलाओं एवं दिव्य चरित्रों का गुणगान किया। कथा के दौरान देवी वैष्णवी जी ने बताया कि, मनुष्य को भगवान के प्रत्येक स्वरूप का पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ स्मरण एवं भजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजा परिक्षित को अपनी मृत्यु का समय ज्ञात था, किंतु आज के मनुष्य को यह नहीं पता कि, जीवन का अंतिम क्षण कब आएगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हर समय प्रभु भक्ति और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर रहना चाहिए। कथा के दौरान भगवान की लीलाओं का हुआ विस्तृत वर्णन किया गया। प्रह्लाद, ध्रुव सहित अनेक भक्त चरित्रों का वर्णन करते हुए भगवान के नृसिंह अवतार, मत्स्य अवतार तथा अन्य दिव्य अवतारों की कथाएं सुनाई गईं। साथ ही भगवान श्रीराम के जीवन प्रसंगों के माध्यम से भाई-भाई के प्रेम और आदर्श संबंधों का महत्व बताया गया।

कार में अवैध शराब जप्त

माही की गूंज, रायपुरिया/पेटलावद।

झकनावदा चौकी पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 30 पेटी अवैध देशी मसाला शराब से भरी एक कार क्रमांक जीजे 05 सीएस 3015 को बिजोरी-रूपाखेड़ा मार्ग से जब्त किया है। चौकी प्रभारी सुरेन्द्रसिंह सिसोदिया ने बताया कि, सोमवार-मंगलवार की सुबह 6 बजे के करिब मुखबीर से सूचना मिली थी कि एक चार पहिया वाहन कार में अवैध देशी मसाला परिवहन की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोकने की कोशिश की उसके पहले ही वाहन चालक मौका देखकर कार छोड़कर मौके से फ्ररार हो गया, बाद वाहन की तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से 30 पेटी अवैध देशी मसाला शराब बरामद हुई। पुलिस ने शराब सहित वाहन को जब्त कर झकनावदा पुलिस चौकी परिसर में खड़ा कराया। पुलिस द्वारा मामले में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि, अवैध शराब कहां से लाई जा रही थी और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था।

कलेक्टर-एसपी ने जिला जेल का किया निरीक्षण

माही की गूंज,झाबुआ।

कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट एवं पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पाटीदार ने जिला जेल का निरीक्षण कर संचालित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बंदियों के आवासीय कक्षों, रसोईघर, पेयजल व्यवस्था, मुलाकात कक्ष सहित जेल परिसर में उपलब्ध अन्य सुविधाओं का अवलोकन किया। जेल प्रशासन से बंदियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान रसोईघर में भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया गया। कलेक्टर एवं एसपी ने बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बंदियों के स्वास्थ्य का नियमित परीक्षण कराया जाए तथा आवश्यकतानुसार उन्हें समय पर चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही जेल परिसर में स्वच्छता, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर जेल अधीक्षक श्री सुजीत खरे, जेल विभाग के अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।

चार धाम यात्रा से सकुशल लौटे यात्रियो का स्वागत

माही की गूंज ,बरवेट।

उत्तराखंड की चार धाम यात्रा यमनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन कर लेते प्रजापत परिवार के 16 सदस्यो का जत्था मंगलवार को बरवेट लोटा। बरवेट के प्रहलाद प्रजापत मोहनी प्रजापत यात्रा से लौटने पर परिवारजनों ने आत्मीय स्वागत किया। इसके साथ कारदावाद से प्रेमचंद प्रजापत, रामीबाई प्रजापत, कुशलगढ़ से शंकर प्रजापत, रायपुरिया से जगदीश प्रजापत, दाखा प्रजापत, हंसराज प्रजापत, पिंकी प्रजापत, बिरमावल से अर्जुन प्रजापत सहित सभी तीर्थ यात्रियों को पुष्प वर्षा कर आत्मीय स्वागत किया। इसके बाद नाचते गाते ढोल के साथ माता पंथवारी की पूजन अर्चन पंडित राजेन्द्र प्रसाद त्रिवेदी ने करवाई। तीर्थ यात्रियों का इस प्रकार का स्वागत करना हर किसी के मुख पर प्रसन्नता देखी जा रही थी।

विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण

माही की गूंज, झाबुआ।

सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग झाबुआ श्रीमती सुप्रिया बिसेन द्वारा पीएमश्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेघनगर एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंतरवेलिया का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान पीएमश्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेघनगर में ग्रीष्मकालीन अवकाश उपरांत श्रीमती सुभदा पंतोजी, श्रीमती नीमा रावत एवं श्री गौरव सिंगल उच्च माध्यमिक शिक्षक दो दिवस के आकस्मिक अवकाश पर पाए गए। किन्तु उनके अवकाश आवेदन की प्रतियां विद्यालय में उपलब्ध नहीं थीं। वहीं श्रीमती उषा नायक, स्थायी कर्मी, ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में अनुपस्थित पाई गईं। इस संबंध में संबंधित प्राचार्य को स्थिति स्पष्ट करने एवं आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। सहायक आयुक्त द्वारा विद्यालय में छात्रवृत्ति वितरण, अपार आईडी तथा ओटीआर की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने संबंधित स्टाफको निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंतरवेलिया के निरीक्षण के दौरान अशोक बुधवन्त, श्रीमती अर्चना चंदेल (उच्च माध्यमिक शिक्षक), श्रीमती सुनीता राजपूत, श्रीमती लाडकी अमलियार (माध्यमिक शिक्षक) एवं श्रीमती ममता भूरिया (प्राथमिक शिक्षक) उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर दर्ज करने के पश्चात निरीक्षण समय पर अनुपस्थित पाए गए। उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा रही है।

जन समस्या निराकरण शिविर का हुआ आयोजन

माही की गूंज, सारंगी।

सारंगी में जन समस्या निराकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 15 आवेदन आए। ब्लॉक से आए सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग की शासन से मिलने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी।

एसडीएम की उपस्थित में शिविर में आय सभी अधिकारियों को निर्देश दिए की जन समस्या निराकरण शिविर में प्राप्त प्रत्येक आवेदन को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ लेते हुए समय मध्य कार्रवाई की जाए। स्वास्थ्य विभाग से बीएमओ डॉक्टर एमएल चोपड़ा ने भी स्वास्थ्य विभाग से मिलने वाली सभी योजनाओं के बारे में बताया। चयनित हितग्रहियों को ग्राम पंचायत एवं महिला बाल विकास द्वारा वृद्धावस्था पेंशन एवं लाडली लक्ष्मी के प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। इस जन समस्या निराकरण शिविर में तहसीलदार अनिल बघेल, सारंगी नायब तहसीलदार अंकिता भिड़े, जनपद सीईओ जीएस चौहान, बीएमओ एमएल चोपड़ा, पेटलावद ब्लॉक से सभी विभाग के अधिकारी, सारंगी ग्राम पंचायत सरपंच फूलंदी बाई मेड़ा , ग्राम पंचायत सचिव हरिराम भूरिया, हलका पटवारी यश रामावत, स्थानीय सभी विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे।

भांजगड़ी प्रथा में उलझा जनजाति समाजः सच्चाई से दूर लाभ उठाते पुलिस और भांजगड़िये

माही की गूंज, झाबुआ। रिंकेश बैरागी

भांजगड़ी प्रथा, जनजाति समाज के लिए एक ऐसा घाव है जो उसे धीरे-धीरे कमजोर करते हुए भ्रष्ट और अपराधिक प्रवृत्ति वाला बना रहा है। जनजाति क्षेत्र के गांवो से किसी भी प्रकरण का मामला पुलिस के पास जाता जरुर है किंतु उस मामले की सुनवाई भांजगड़ियों द्वारा लेन-देन की प्रक्रिया के साथ होती है। जिसमें पुलिस का बराबर हिस्सा होता है। क्योंकि लेन-देन की प्रक्रिया, उसकी बातचित सभी कुछ पुलिस के सामने की जाती है। अगर बातचित में कोई समस्या रहती है तब शक्तिशाली पक्ष एफआईआर करवाने की धमकी के साथ पुलिस से भी जोर लगवाता है और पुलिस अपनी जेब भरने के चक्कर में भांजगड़िये की सुनकर उसके अनुरुप काम करने लगती है। मामले को दबाने के लिए मुंह मांगी रकम तय होती है, यह रकम हजारों से शुरु होकर लाख तक पहुंच जाती है। जिसका कोई रिकार्ड किसी के पास नहीं होता कि, एक पक्ष द्वारा दी गई रकम कब किसकी झोली में समा गई। वहीं दूसरे पक्ष से भी उसी प्रकार तय की गई राशि का बंटवारा होता है।

हालांकि यह स्थिति जनजाति क्षेत्र में ही फलफुल नहीं रही बल्कि पूरे प्रदेशभर और देशभर में इस प्रथा ने अपनी जड़े शक्तिशाली कर ली है। परंतु जनजाति क्षेत्र में इसका प्रकोप बहुत ज्यादा है। छोटे से छोटे केस में ग्रामीण को 40 से 50 हजार की हानि हो जाती है। यह सिर्फ भांजगड़ियों के साथ मिली हुई पुलिस के लोभ-लालच के कारण होता है। भांजगड़ियों के कहने पर पुलिस भोलेभाले ग्रामीणों को एफआईआर का डर बताकर कोर्ट के चक्कर और जेल जाने तक की बात से भयभीत करते हैं। और गलती में नहीं होने के बाद भी कुछेक प्रकरणों में ग्रामीणों को दूसरे पक्ष और पुलिस को समझौते के नाम पर मांगी गई राशि देनी पड़ती है। वर्तमान में नियमों के उल्लघंन से लगाकर मारपीट, चोरी-चकारी और अन्य अपराधों को करने में किसी को संकोच नहीं होता है। यदि ग्रामीणों से अपराध हो गया तो उन्हें पता है कि, किए गए अपराध का पैसा देना होगा और मामला वहीं का वहीं दबा दिया जाएगा। न किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट होगी न ही किसी को अपराधी बनाया जाएगा।

इस भांजगड़ी प्रथा के चलते लोग पैसो के मारे पिसाते भी है, एक बड़ी रकम भांजगड़ियों को देनी होती है, और बहुत से लोगों के मन से डर खत्म हो जाता है। क्योंकि वो लोग इस बात को समझ जाते हैं कि, अगर किसी प्रकार का कोई अपराध हो गया तब दूसरे पक्ष को भांजगड़िये और पुलिस का पैसा देना होगा। इसी प्रकार जब कोई विवादित स्थिति सामने आती है तब वह लोग उस स्थिति को सामान्य नहीं करते, अपितु अपने अहम में आकर अपराध कर देते हैं। अपने लालच में पुलिस, खाकी की शक्ति का दुरूउपयोग कर इस पुरे क्रम को देखते रहते हैं और जब स्थिति उनसे बाहर की दिखाई देती है तब वह अपनी जान बचाने के लिए नियमों का उपयोग करते हैं।

जनजाति क्षेत्र में आए दिन विवाद, जमीनी लड़ाई, नशा, मारपिट, दुर्घटना, प्रेम प्रसंग में घर से भागे हुए लड़का-लड़की के प्रकरण की अधिकता रहती है। इन सभी प्रकरणों के अपने-अपने क्षेत्र के अनुसार समझौते की राशि निर्धारित होती है, और भांजगड़ियों की बातचित भी पुलिस से बराबर की होती रहती है। किसी प्रकरण में कोई पैसा देने में दुरी कर रहा है या कोई और कारण में फंसता है तब पुलिस सीधे एफआईआर की बात करती है और मामले को सुलझाने में समय लगाती है। अगर किसी पक्ष की किसी बड़े नेता या किसी अधिकारी से पहचान होती है तब भी मामला उतना जल्दी नहीं सुलझ पाता जितना जल्दी उसे एक भांजगड़िया सुलझा लेता है।

पुलिस और भांजगड़ियों को दोनों पक्षों से लाभ की प्राप्ति होती है, अब अगर इस मध्यस्थता वाले खेल को खत्म करना है तो पुलिस को आगे कदम बढ़ाना होगा और समझौते के लिए भांजगड़िये को न चुनते हुए न्यायालय को प्राथमिकता देना होगी। इस पहल से अपराध करने वाले के मन में कानून का भय आएगा और जिनसे अनजाने में अपराध हुआ होता है वे अगली बार अपराध करने से बचेगें।

भांजगड़िये द्वारा समझौता करवाने पर लाभ सिर्फ पुलिस और भांजगड़िये को ही होता है, और उस समझौते में समझाइश भी नहीं होती है कि, दोनों पक्ष अगली बार कोई गलती नहीं करेगा। फिर समझाइश का दौर चल भी नहीं सकता क्योंकि जब दोनों पक्ष पैसा दे रहे हैं तो वे क्यों किसी की सुनेगें। इसीलिए समस्या का समाधान यह है कि, यदि कोई अपराध हुआ है और उसमें दोनों पक्ष आपसी समझौता चाहते है तो वे न्यायालय की शरण ले।

इस प्रथा में भी अपने लोग ही अपनो को लूट रहे हैं। गांव का भांजगड़िया कोई और नहीं होकर गांव का तड़वी, पटेल या सरपंच या फिर मुखिया ही होता है। भांजगड़ियां गांव का ही होता है इसीलिए उसे सभी के नाम, उनका स्तर पता होता है और वह अपने लालच में पुलिस को बताता है कि, पैसे की डिमांड का प्रारुप क्या होगा।

एक साधारण सी दुर्घटना के केस को न्यायालय के माध्यम से करने पर भी पुलिस ने अपने काम करने के अधिकार की मेहनत को मांग लिया जाता है। इसी तरह हर विभाग में स्थिति ऐसी ही है, पैसा फैको तमाशा देखो। अपना काम करवाने के लिए सभी को पैसा देने पड़ता है। राजस्व विभाग द्वारा तहसील कार्यालय का छोटा कर्मचारी भी भूमी को नापने के लिए खर्चा पानी लेता है। बहरहाल, यह पैसा दिखाई नहीं देता, कहा से आता है किसके पास रुकता है वहां से कहां चला जाता है। इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं रहता। राज तो उस समय खुलते हैं जब किसी के पास पहुंचने वाली राशि में गड़बड़ी हो जाती है और फिर एक के बाद एक मामले सामने आते-जाते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए समाज का उद्धार करने वालों को सामने आ कर समझाइश देना होगी कि, गलत कार्यों से बचो, अपराध करने से बचो, यदि अज्ञानतावश अपराध हो जाए तो न्यायालय की शरण ली जाए।

सीसीटीवी में बाइक ले जाता दिखा चोर।

पूर्व मंडल अध्यक्ष की गाड़ी चोरी, चोर सीसीटीवी में कैद, आठ दिन बाद भी पुलिस रही विफल

माही की गूंज, पेटलावद/रायपुरिया।

चोरों के हौसले कितने बुलंद है इसी से पता चलता है कि, जो चोर पहले रात के अंधेरे में चोरी की घटना को अंजाम देते थे अब दिन दहाडे चोर वारदात कर पुलिस को चुनौती देते है। वारदात रायपुरिया थाना क्षेत्र की है जहां पर पूर्व मंडल अध्यक्ष रायपुरिया मंडल के शांतिलाल मुणिया ने अपना दुपहिया वाहन एमपी 45एमटी 7260 रायपुरिया हनुमान मंदिर के बाहर खड़ा किया। जिसके बाद अपने रिश्तेदारों के साथ पारिवारिक कार्य से ग्राम झावलिया गए थे। जहा सुबह दस बजे वाहन खड़ा कर एक बजे लौटे लेकिन वाहन वहां नहीं मिला। वाहन को काफी ढूंढने के बाद जब वाहन नहीं मिला तो रायपुरिया थाने में वाहन चोरी का मामला दर्ज करवाया।

सीसीटीवी में कैद चोर

मंदिर के आसपास तो सीसीटीवी नहीं थे लेकर बेखौफ चोर चोरी कर वाहन को बीच बाजार से पुलिस थाना रायपुरिया के सामने से लेकर निकला ओर इस बीच नगर ओर थाने के सीसीटीवी में चोर वाहन ले जाता दिखा। चोर मुख्य मार्ग से होता हुआ रामनगर के बाद आगे वाले गांवों में लगे सीसीटीवी में नहीं दिखा। घटना 2 जून की है लेकिन 8 दिन बाद भी रायपुरिया पुलिस वाहन की खोज नहीं कर पाई।

पूर्व मंडल अध्यक्ष ने बताया कि, वाहन चोरी होने के बाद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज बताए लेकिन अब तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। सत्ता धारी दल के नेता के वाहन की चोरी की घटना को लेकर पुलिस सुस्त है तो आम जनता के साथ होने वाली वारदातो को लेकर पुलिस का क्या रवैया रहता होगा?

संतों के दर्शन से साधक हो जाता है रिचार्ज-मुनि श्री

माही की गूंज, थांदला।

अहिंसा प्रधान जैन धर्म के साधक तप व संयम से मोक्ष का सफर तय करते है। ऐसे में थांदला में चल रहे सामूहिक वर्षितप आराधकों के उत्साह में अभिवृद्धि करने व उनके तप की निर्मलता बनी रहे इस हेतु उन्हें सही दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से मोहनखेड़ा महातीर्थ प्रणेता जैनाचार्य प.पू गुरुदेव श्रीमद्विजय ऋषभचन्द्र सूरीश्वरजी म.सा?. के आज्ञानुवर्ती सुशिष्य अष्टम वर्षीतप तपस्वी प. पूज्य मुनिराज श्री पीयूषचन्द्र विजयजी म.सा. एवं पूज्य मुनिराज श्री रजतचन्द्र विजयजी म.सा. ने पारणा स्थल स्थानीय महावीर भवन पर पहुँच सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हुए आशीर्वचन दिए।

इस अवसर पर मुनि श्री पियुषविजय ने कहा कि, प्रथम राजेश्वर, प्रथम मुनि, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेवजी के अंतराय निदान रूप वर्षितप की आराधना की जाती है। ऐसे में साधकों को पूर्ण सावधान रहते हुए अपनी इच्छाओं का निरोध करना होता है इसलिए तप करना आसान नही होता। आजकल जैन समाज में भी विकृति आ गई है अतः रात्रि भोजन को फैशन समझते है। अन्य जनों को तो छोड़ो आजकल तो तपस्वियों के घर में भी रहने वालें श्रावक-श्राविका में भी तप के प्रति अनुमोदना के भाव नही बनते व वे छोटा सा तप करने से भी परहेज करते है। ऐसे में वर्षितप के तपस्वी धन्य है जो वर्ष भर नियम में रहकर अपने तप को पूर्ण कर रहे है। मुनिश्री ने बातों ही बातों में हित शिक्षा देते हुए कहा कि, तप में इच्छाओं का निरोध परम आवश्यक है इसलिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखें। क्योंकि संसारी तो क्या संत भी इस रस की आसक्ति से बच नही पाए है। आपने कहा जिस तप में संयम का समावेश हो जाता है, वह तप मोक्ष दिलाने वाला बन जाता है। आपने सभी तपस्वियों से कहा कि प्रसन्नता से संत मुनिराज को निर्दोष आहार दान व तप सहयोगियों के प्रति धन्यवाद के भाव तप को और महान बनाते है। आपने धर्मधरा थांदला में जन्में जैनाचार्य पूज्य श्री उमेशमुनिजी म.सा. का जिक्र करते हुए कहा कि उन जैसा विशिष्ट साधक व उनकी संत परंपरा से प्रेरणा लेकर सकल जैन समाज व जेनेत्तर बंधु तप के द्वारा कर्मो की कोड़ खपा रहे है यह निश्चित ही अनुमोदना का विषय है। आपने कहा जैसे मोबाइल में रिचार्ज डलवा दिया जाये तो नेटवर्क मिलता है, वैसे ही संत समागम उनके दर्शन वंदन से आराधक भी रिचार्ज हो जाता है व दोगुने उत्साह से वह तप में आगे बढ़ता है।

पुरषोत्तम मास में गौदान करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है

माही की गुंज, बरवेट।

पुरषोत्तम मास में गौ दान करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, यह बात समीपस्थ ग्राम बनी में स्थिति श्रीकृष्ण काम धेनु गौशाला में आयोजित गोदान कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि पुरषोत्तम मास या अधिक मास में गौ दान करना अत्यंत पुण्यकारी और मोक्षदायक माना जाता है। इस पवित्र महीने में दान करने से आपके सभी पाप मिट जाते हैं। गौदान में ज्येष्ठ मास की सत्तमी का विशेष महत्व होता है। इस दिन गौ दान करने से भगवान भगवान पुरषोत्तम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सभी दान में गोदान को सबसे बड़ा दान माना गया है। इस पवित्र महीने में दान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। साथ कल्पवृक्ष के वृक्ष के नीचे गौदान करने से भगवान पुरुषोत्तम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस मनुष्य जीवन में आए हो तो एक बार जरूर गोदान करना चाहिए। जिससे आपके जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते है।

गौ दान का लाभ लिया

श्रीकृष्ण काम धेनु गौशाला ग्राम बनी में गौदान का उत्सव के आयोजन किया गया। जिसमें मनासा, मुंबई के समाज सेवी गोपालकृष्ण लड्डा परिवार ने गौदान कर पुण्य लाभ लिया। इससे पहले यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ में हरिहर आश्रम के पीठाधीश्वर आचार्य डा देवेंद्र शास्त्री धारिया खेड़ी मंदसौर वाले ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रमुख जजमान परिवार से यज्ञ में आहुतियां दिलवाई। इसके बाद गौशाला में लगे कल्प वृक्ष के नीचे ले जाकर विधि-विधान से गौ माता का दान करवाया। इससे पहले गौ माता की पूजन अर्चन की गई इसके बाद यजमान द्वारा गौमाता की पूछ पकड़कर वेतरनी नदी पर करने की रस्म को निभाया। इस अवसर पर गौशाला समिति के सदस्य हरिओम पाटीदार, हरिराम पाटीदार शिक्षक, राधेश्याम पाटीदार, शांतिलाल पाटीदार, गोविंद पाटीदार, रामेश्वर पाटीदार, मुकेश पाटीदार, रमेश भटेवरा, अशोक भटेवरा, मुकेश हांडीकुंडी, मोहनलाल पाटीदार, गौरधनलाल पाटीदार राजू भगत, रामलाल जी पाटीदार सहित सेकडो की तादात में ग्रामीण जन उपस्थित थे।

मोहर्रम करीब आने से ताजिया निर्माण में तेजी

माही की गूंज, झाबुआ।

मुस्लिम क्षेत्र में ताजियों को बनाने के काम में कारीगर बड़ी तेजी से जुटे हैं। मोहर्रम माह करीब आ जाने से ताजिया निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। छोटे-बड़े तमाम ताजियों को मोहर्रम की नौवीं को राजवाड़ा चौक पर रखा जाएगा।

ताजिया निर्माण करने वाले मोईब शेख व रईश शेख ने बताया कि, ताजियादारी की परंपरा वर्षों से निभाई जा रही है। शहर में मोहर्रम के दौरान ताजिया आकर्षण का केंद्र रहता है। मोहर्रम माह जल्द शुरू होने वाला है ऐसे में ताजियों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही वर्षा से बचाने के लिए इमामबाड़े पर भी व्यवस्था की गई है। आकर्षक व बारीक कारीगरी से ताजिए तैयार किए जा रहे है। ताजिया कमेटी के युवा जुनेद शेख, फरदीन शेख, मोहसीन शाह, नईम शेख, ताजिम (लड्डू) कुरैशी, आदिल शेख, रेहान शाह (बाबू), कासिम शेख, मिरान शेख, अरबाज खान, फरहान शाह, रेहान शाह, यासिन खान, अयान शेख समेत कई युवा प्रतिदिन देर रात तक ताजिया निर्माण कार्य कर रहे है।

निकाला जाता है जुलूस

आतिफ खान व करीम शेख ने बताया कि इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक, मुहर्रम इस्लाम धर्म का पहला महीना होता है। मुहर्रम के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग गमजदा होकर शोक मनाते हैं। इस दिन मुसलमान लोग हुसैन की शहादत को याद करते हैं और उनके प्रति अपना शोक व्यक्त करते हैं। इसको लेकर युवाजनों ने आकर्षक ताजियों का निर्माण प्रारंभ कर दिया है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को हुसैन की शहादत की याद में जुलूस के रूप में ताजिया निकाला जाता है।

ऐसे बनते है ताजिये

ताजिया निर्माण कमेटी के जावेद शाह व अजहर शेख ने बताया कि, इस्लाम धर्म के लोगों के लिए यह महीना बहुत अहम होता है। क्योंकि इसी महीने में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। हजरत इमाम हुसैन इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मुहम्मद साहब के छोटे नवासे थे। उनकी शहादत की याद में मुहर्रम का पर्व मनाया जाता है यह महीने के दसवें दिन जिसे आशूरा भी कहा जाता है। इमाम हुसैन की याद में मनाए जाने वाले रोजे का प्रतीक के रूप में बनाई जाने वाली बड़ी-बड़ी कलाकृतियों को ताजिया कहा जाता है। इसको बनाने में लकड़ी, बांस, स्टील, कपड़े, मिट्टी, कागज, थर्माकोल आदि सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है।

संपादकीय

विकास की प्राथमिकताओं में बरतें सावधानी

आज वैश्विक आर्थिक परिदृश्य तेजी से अनिश्चितता के भंवर में फंसता नजर आ रहा है। अमेरिका-इस्राइल व ईरान के बीच जारी संघर्ष से उपजा भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि, बाधित व्यापार मार्ग से प्रभावित आपूर्ति श्रृंखला भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये नई चुनौतियां खड़ी कर रही है। ऐसे में देश के लिये प्राथमिकता केवल विकास की गति बनाये रखना ही नहीं होनी चाहिए। सरकार का दायित्व है कि आम लोगों को महंगाई की मार से बचाने के लिये व्यावहारिक कदम भी उठाये। दरअसल, भारत के सामने केवल मध्यपूर्व में जारी संघर्ष से उपजा संकट ही नहीं है, बल्कि अंदरूनी मोर्चे पर भी कई तरह की दिक्कतें पैदा हो रही हैं। हाल ही में केंद्रीय बैंक ने देश में मानसून में कमी की आशंका जतायी है। ऐसा अल-नीनो के प्रभाव के चलते पैदा होने वाले विषम हालातों के चलते कहा गया है। जिसके चलते आगामी कुछ माह में खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। ऐसे में महंगाई में कमी आने की सूरत नजर नहीं आती। देश के कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि फिलहाल सरकार की प्राथमिकता आर्थिक विकास में वृद्धि ही है। जिसके चलते आशंका जतायी जा रही है कि इससे नागरिकों पर महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। निस्संदेह, अर्थव्यवस्था में सुधार होना चाहिए, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए आम आदमी को महंगाई से राहत देना बेहद जरूरी है। अन्यथा आम लोगों का जीवन-यापन और अधिक कष्टकारी भी हो सकता है। यही वजह है कि कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि सरकार आर्थिक विकास की प्राथमिकताओं व महंगाई नियंत्रण के प्रयासों के बीच संतुलन साधने का प्रयास करे। लेकिन पिछले दिनों पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में कई बार की वृद्धि के बाद व्यावसायिक व घरेलू एलपीजी के दामों का बढ़ना, लोगों की चिंता बढ़ाने वाला है। जाहिर बात है कि इस वृद्धि से पहले ही महंगाई से जूझते लोगों का बजट और गड़बड़ा जाएगा। निस्संदेह, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में वृद्धि के बाद कुकिंग गैस के दामों की वृद्धि आम आदमी का बजट बिगाड़ने वाली है। फलतरू लोगों की क्रय शक्ति कम हो रही है। वहीं आर्थिकी में मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ने की आशंका है। इस उथल-पुथल भरे वैश्विक परिदृश्य में कुछ कारक देश की अर्थव्यवस्था को संबल देने वाले भी हैं। देश में घरेलू मांग मजबूत है, संरचनात्मक विकास में निवेश जारी है। वहीं तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था हमारी ताकत भी है। जिससे हम एक सीमा तक वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हमारे आयात बिलों पर दबाव बढ़ा रही हैं। जिसका प्रभाव रुपये पर भी बढ़ते दबाव के रूप में सामने आया है। हालांकि, विदेशी संस्थागत निवेशकों को लुभाने के लिये केंद्रीय बैंक प्रयासरत है, लेकिन बाजार के पटरी पर आने में कुछ वक्त अवश्य लगेगा। आरबीआई का विश्वास है कि निवेश नियमों में ढील से पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्रीय बैंक की प्राथमिकताओं में आर्थिक स्थिरता कायम करना, रुपये को संबल देना और देश की वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त तरलता बनाये रखना भी है। बैंक की कोशिश है कि विकास को प्रभावित किए बिना ही आर्थिक स्थिरता लाने का प्रयास हो। निस्संदेह, नीति-नियंताओं के सामने आर्थिक विकास को गति देने के साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना भी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिये दोनों में संतुलन बनाने की जरूरत है। हम विकास और रोजगार को संरक्षण देते हुए महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास करें। जिसके लिये राजकोषीय विवेक, कमजोर वर्ग के लोगों को संबल तथा संरचनात्मक सुधार प्राथमिकता हों। तभी आर्थिक विकास और महंगाई में संतुलन बनाने में सफलता मिल सकती है। इसके लिये सरकार को अतिरिक्त कदम उठाने होंगे। वह महसूस करे कि आम आदमी की जेब पर महंगाई दबाव बनाने लगी है। जिससे अर्थव्यवस्था का प्रभावित होना लाजमी है। जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने देश की आर्थिक वृद्धि दर में न केवल कमी की है बल्कि खुदरा महंगाई दर में वृद्धि के भी संकेत दिए हैं। विश्वास करें कि सरकार मौजूदा संकट से मुकाबले हेतु विस्तृत व्यावहारिक कदम उठाएगी।

कॉकरोच पार्टी के मुद्दे और पंजाब में उनकी प्रासंगिकता

निर्मल संधू

भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई एक टिप्पणी, शायद गैर-इरादतन, के परिणामस्वरूप 'कॉकरोच जनता पार्टी' का अप्रत्याशित उद्भव हुआ है, पहले डिजिटल स्वरूप में और अब साक्षात रूप में भी। इसने युवाओं को अपनी ओर खींचा है, खासकर उन्हें जो शिक्षा में हुई धांधलियों से नाराज हैं या जो बेरोजगार हैं या जो कम तनख्वाह की नौकरियों में जीवन निर्वाह के लिए जूझ रहे हैं।

पंजाब को ज्यादा चिंता करनी चाहिए क्योंकि अक्तूबर-दिसंबर 2025 के अवधिक श्रम सर्वे के मुताबिक, सूबे की युवा बेरोजगारी दर 19 फीसदी के साथ काफी अधिक है। चिंतनीय, कि यह अखिल भारतीय औसत (14.8 प्रतिशत) से ज्यादा है। इसकी तुलना में, हरियाणा में बेरोजगारी दर घटकर 12.4 फीसद रह गई।

ऐसा क्यों है, यह सवाल पंजाबी पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान, जिन्हें मीडिया की सुर्खियों में रहना पसंद है और जो अकसर अकाली और कांग्रेस विरोधियों का मजाक उड़ाते हैं, शायद इसका जवाब न दे पाएं। वे करीब 66,000 नौकरियां देने की शेखी बघारते हैं, लेकिन उस दौरान सेवानिवृत्त हुए लोगों की वजह से पैदा रिक्तियों की बात नहीं करते।

नौकरियां तब पैदा होती हैं, जब विकास हो। पंजाब की 6.1 विकास दर राष्ट्रीय औसत 7.4 फीसदी से नीचे है। जबकि रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर को घटाकर 6.6 फीसदी किया है। खाद की कमी और महंगे हुए वाहन ईंधन की वजह से खेती और उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव से पंजाब को बड़ा नुकसान हो सकता है। महंगाई दर बढ़ने से सामाजिक चिंताएं बढ़ेंगी।

युवाओं के लिए स्थिति कुल मिलाकर बदतर होती जा रही है। डॉलर के मुकाबले गिरता रुपया जहां विदेश यात्रा और पढ़ाई को मध्य वर्ग की पहुंच से बाहर कर रहा वहीं विदेश जाकर बसने के लिए कनाडा व अमेरिका जैसे उनके पसंदीदा देश आप्रवासियों के लिए द्वार बंद कर रहे हैं। ब्रेन ड्रेन के नुकसान को एक तरफ रखें तो अगर इन देशों ने महत्वाकांक्षी युवा पंजाबियों को पलायन के बेहतर रास्ते मुहैया न कराए होते तो पंजाब में गंभीर सामाजिक उथल-पुथल देखने को मिल सकती थी।

बिगड़ते आर्थिक माहौल और सिकुड़ती विदेशी राहों के असर का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। लेकिन क्या पंजाब इस उभरती कड़वी सच्चाई का सामना करने को तैयार है? अपने भविष्य को लेकर उम्मीदें खोकर, युवा नशीले पदार्थों की ओर रुख करते हैं या कभी-कभार बंदूक उठा लेते हैं। नशा और गैंगस्टर रूपी समस्याएं समाज-व्यवस्था में व्याप्त सड़न की ओर इशारा करती हैं। सरकारी एजेंसियां सिर्फ लक्षणों से जूझ रही हैं। वही नेता, जिनके पास पुराने समाधान हैं, समस्याओं का निदान नहीं कर सकते। बीते शनिवार दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉक्रोच जनता पार्टी' के धरने ने राजनीतिक वर्ग के प्रति युवाओं का अविश्वास दर्शाया। ऐसे लोकतांत्रिक आंदोलन कभी-कभी नूतन विचार युक्त नए नेता उभारते हैं। 'कॉक्रोच जनता पार्टी' की लोकप्रियता सियासी दलों को पुराने नेताओं की जगह नए होनहार चेहरे लाने को मजबूर कर सकती है। युवाओं के मुद्दे अभी न तो पंजाब में विपक्षी दलों की चुनाव नीति में शामिल हैं और न ही सत्ताधारी 'आप' की। अधिकांशतः काम चलाऊ फौरी समाधानों के भरोसे रहकर भगवंत मान बड़ी गलती कर रहे हैं। मुफ्त की रेवड़ियां लुटाकर, वे भविष्य की जलधारा में छिपे हिम-शैलों को नजरअंदाज कर, नाजुक किश्ती पर सवार हैं। वोटरों पर लुटाया जाने वाला पैसा, ठप पड़े उद्योगों, ठहरी हुई खेती और खराब सेवाओं में फिर से जान फूंकने में खर्च किया जाना चाहिए। अगर सीमित साधनों का इस्तेमाल समझदारी से विकास करने पर किया जाए, तो राजनीतिक फायदा होने में समय अवश्य लग सकता है लेकिन मिलता जरूर है। केवल अर्थपूर्ण एवं गुणवत्ता वाली कारगुजारी ही समृद्धि व कर-वसूली बढ़ा सकती है, जिससे राज्य को जरूरतमंदों की मदद करने में सहायता मिल सकती है। कर्ज लेकर भलाई कार्य करना सामान्य समझ से परे है। सबको मुफ्त में रेवड़ी बांटना अकर्मण्यता को बढ़ावा देता है। खाते-पीते पंजाबी भी राज्य पर निर्भर होकर आत्म-सम्मान खो रहे। कांग्रेस सांसद धर्मवीर गांधी ने इस बिंदु को जोर देकर उठाया है।

लगता है, सियासी दल अतीत से कुछ नहीं सीख रहे। उदार सब्सिडी और करदाताओं के पैसे का भारी मात्रा में इस्तेमाल खुद के प्रचार, वीआईपी सुरक्षा और हेलीकॉप्टर पर करने के बावजूद, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह, दोनों ही, चुनाव हार गए थे।

हालिया निकाय चुनाव सबूत हैं कि 2027 के विधानसभा संग्राम में असल मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा। यदि भाजपा पंजाब के लिए कोई भरोसेमंद आर्थिक मॉडल प्रस्तुत कर पाए, तभी सत्ता की गंभीर दावेदार बन सकती है। पंजाब में नए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों, उद्योग और उसकी समस्याएं- जिस विषय की समझ उन्हें ज्यादा हो सकती है- पर बोलने के बजाय, जब राजनीतिक बयानबाजी और महाराजा रणजीत सिंह के खालसा राज की बातें करते हैं, तो यह उनका जमीनी हकीकत से कटे होना दर्शाता है।

अंदरूनी कलह से पीड़ित कांग्रेस को ठोस दलील पेश करनी होगी कि उसे सत्ता क्यों सौंपी जाए, जबकि उसका हर वरिष्ठ नेता सर्वोच्च पद के लिए 'पहले मैं' का खेल खेल रहा है। राहुल गांधी, बेशक, 'कॉकरोचों' के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन क्या उनके दल के पास युवाओं के लिए कोई स्पष्ट योजना है? एआई से नौकरियों को खतरा बन गया है। क्या उनकी पार्टी ने इस मुद्दे पर गंभीर विचार किया? कौन सा नेता ज्यादा वोट दिला सकता है इस हेतु पता लगाने को सर्वे करना काफी नहीं। पंजाब में पार्टी की डाल और जड़ स्तर पर कारगुजारी का पुनरावलोकन करने की जरूरत है। आजमाए-असफल नेताओं की जगह उन लोगों को लाए, जिनके पास नजरिया हो, ऊर्जा से लबरेज हों और पंजाब के पुनरू विकास में मददगार हो सकें।

सत्ताधारी दल होने के नाते, आम आदमी पार्टी उच्च पायदान पर है। लेकिन कुछ चमक खो चुकी है। 'आप' सरकार इस कदर प्रचार-चालित है कि उसकी हर उपलब्धि पर संशय करना पड़ रहा है। उसके बहु प्रचारित नशा-निरोधक अभियान की सफलता जमीन पर महसूस नहीं हो रही।

जहां यह श्रेय वाकई भगवंत मान सरकार को जाता है कि स्टेडियम बनवाए और खेलों को बढ़ावा दे रही वहीं सबसे बड़ी उपलब्धि शिक्षा क्षेत्र में पाई है। नीति आयोग ने अपनी नवीनतम स्कूली शिक्षा व्यवस्था रिपोर्ट में पंजाब को प्रथम स्थान दिया। यह वर्ष 2020 के 27वें स्थान से एक बड़ी छलांग है । इस सफलता का श्रेय प्रचारबाजी शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस के अलावा 'आप' के केंद्रीय नेता मनीष सिसोदिया को भी जाता है।

हालांकि, कॉलेज-यूनिवर्सिटी स्तर की शिक्षा में चुनौतियां बरकरार हैं। विगत की सरकारों ने निजी शिक्षा संस्थानों की तरक्की की एवज में सरकारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को फंड से वंचित रखा। नतीजन, खर्च में भारी बढ़ोतरी ने उच्च शिक्षा को निम्न-मध्य वर्ग के छात्रों की पहुंच से दूर कर दिया। स्वास्थ्य क्षेत्र हो, शिक्षा या फिर रोजगार, नुकसान में ज्यादातर ग्रामीण युवा रहता है। जीवनयापन की बढ़ती लागत के चलते युवा और किसान का कभी-कभी रोष उजागर होता है।

हालांकि, बेरोजगारों को परजीवी ठहरा कर उपहास उड़ाने की प्रतिक्रिया हो सकती है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सरकारों को युवाओं की समस्याओं को गंभीरता से न लेने के जोखिमों से सतर्क हो जाना चाहिए। रोष बढ़ने से रोकने में त्वरित उपाय मददगार होंगे।

राजनीतिक रुझान में दिखे बदलाव के संकेत

के.एस. तोमर

हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न नगर निगम और जिला परिषद चुनावों ने राज्य की राजनीति को नई दिशा दे दी है। इन चुनाव परिणामों की शुरुआत में केवल स्थानीय निकायों तक सीमित माना जा रहा था। लेकिन परिणाम आने के बाद जाहिर हुआ कि जनता ने इन्हें सरकार के कार्य प्रदर्शन और राजनीतिक नेतृत्व की परीक्षा के रूप में देखा। भारतीय जनता पार्टी की निर्णायक बढ़त ने सत्तासीन कांग्रेस सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष राजनीतिक चुनौतियां समय से पहले गहराती दिखाई देने लगी हैं। राज्य कांग्रेस सरकार का कार्यकाल अभी बाकी है लेकिन चुनावी परिणामों ने संकेत दिया कि जनता के एक वर्ग में धीरे-धीरे असंतोष पैदा हो रहा है। भाजपा ने इन नतीजों को सरकार के खिलाफउभरते जनमत के रूप में पेश किया। यह संदेश देने की कोशिश की कि राज्य की राजनीतिक हवा बदलनी शुरू हो गई है।

जिला परिषद चुनावों के परिणाम भाजपा के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि बनकर उभरे। कुल 253 सीटों में से 143 सीटों पर जीत दर्ज कर पार्टी ने स्पष्ट बढ़त हासिल की, जबकि कांग्रेस 59 सीटों तक सीमित रह गई। यह अंतर केवल चुनावी आंकड़ा नहीं, बल्कि ग्रामीण राजनीति में बदलते समीकरणों का संकेत माना जा रहा है। भाजपा अब दावा करने लगी है कि सरकार के खिलाफ नाराजगी शहरी इलाकों तक सीमित नहीं रही, बल्कि गांवों तक फैल रही है।

बिलासपुर में भाजपा का प्रदर्शन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा के गृह जिले में पार्टी ने जिला परिषद की सभी सीटें जीतकर कांग्रेस का सफाया कर दिया। इस जीत ने नड्डा के प्रभाव को फिर दर्शाया है। राज्य में अब भविष्य की राजनीति को लेकर नई चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। हमीरपुर के परिणामों ने भी कांग्रेस

की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मुख्यमंत्री के गृह जिले में भाजपा ने प्रभावी प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस को करीब हाशिये पर पहुंचा दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहां सक्रिय रहे जो भाजपा का माहौल बनाने में मददगार रहा। सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस संगठन जमीनी स्तर पर अपेक्षित मजबूती नहीं दिखा सका। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आक्रामक चुनावी अभियान के दौरान कई बड़ी गारंटियां दी थीं। महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर किए गए वादों ने कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब विपक्ष इन्हीं गारंटियों को सरकार की बड़ी राजनीतिक कमजोरी में बदलने की कोशिश कर रहा है।

भाजपा ने पूरे चुनाव प्रचार में यह नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास किया कि कांग्रेस अपने अधिकांश वादे पूरा करने में विफल रही। स्थानीय मुद्दों के साथ-साथ बेरोजगारी, प्रशासनिक सुस्ती और विकास कार्यों में देरी जैसे विषयों को विपक्ष ने प्रभावी ढंग से उठाया। कांग्रेस सरकार अपनी योजनाओं और फैसलों का राजनीतिक लाभ जनता तक पहुंचाने में कमजोर दिखाई दी।

सरकार की ओर से कई कल्याणकारी कदमों की घोषणा जरूर हुई, लेकिन राजनीतिक संवाद की कमी के कारण उनका प्रभाव अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंचा। यही वजह रही कि भाजपा जनता में यह धारणा बनाने में सफल होती दिखी कि सरकार और लोगों के बीच दूरी बढ़ रही है।

साल 2022 विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा संगठन में निराशा का माहौल था, लेकिन स्थानीय निकाय चुनावों ने पार्टी को नई ऊर्जा दे दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चुनावी रणनीति को स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रखा। भाजपा ने राष्ट्रीय राजनीति के बजाय प्रशासनिक कमजोरी, अधूरी घोषणाओं और जन असंतोष को हथियार बनाया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बूथ स्तर के नेटवर्क ने भी भाजपा की चुनावी तैयारी को मजबूती दी। पार्टी अब यह मानने लगी है कि यदि यही राजनीतिक माहौल बना रहा तो सत्ता विरोधी भावना 2027 से पहले ही अधिक तीव्र हो सकती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भाजपा अभी भी राज्य में सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी मान रही है।

मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए यह स्थिति केवल राजनीतिक चुनौती नहीं, बल्कि प्रशासनिक परीक्षा भी बनती जा रही है। यदि कांग्रेस इन नतीजों को केवल स्थानीय चुनावों तक सीमित मानकर नजरअंदाज करती है, तो सरकार और जनता के बीच अविश्वास की खाई और गहरी हो सकती है। कांग्रेस नेतृत्व को अब तेजी से संगठनात्मक तालमेल मजबूत करना होगा। साथ ही चुनावी गारंटियों के क्रियान्वयन, युवाओं के बीच भरोसा बहाल करने और मध्य वर्ग की नाराजगी कम करने की दिशा में प्रभावी राजनीतिक संदेश देना होगा। आने वाले महीनों में सरकार की सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वह प्रशासनिक फैसलों को राजनीतिक समर्थन में कैसे बदले।

2027 विधानसभा चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि स्थानीय निकाय चुनावों ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति का मूड बदल दिया है। भाजपा आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। राज्य की राजनीति आने वाले समय में और अधिक तीखी तथा प्रतिस्पर्धी होने के संकेत दे रही है।

महिलाओं को ज्यादा झुलसाती है गर्मी की तपिश

मुकुल व्यास

भीषण गर्मी आज एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। दुनियाभर में हर साल लगभग 490,000 लोग गर्मी से अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन ये आंकड़े महिलाओं की रोजमर्रा की जिंदगी पर गर्मी के खतरनाक असर को नहीं दर्शाते। एक नए अध्ययन ने एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया के उदाहरणों के हवाले से बताया है कि महिलाओं को गर्मी के हालात में सबसे ज्यादा एडजस्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन जलवायु संबंधी नीतियों में उन्हें सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया के कई हिस्सों में महिलाएं घर की मुख्य देखभाल करने वाली होती हैं। वे अक्सर पुरुषों के मुकाबले घर के अंदर ज्यादा समय बिताती हैं। उन्हें कम हवादार घरों में बिना इंसुलेशन या कूलिंग के रहना पड़ता है, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक तनाव होता है। इससे पता चलता है कि बहुत ज्यादा गर्मी महिलाओं की सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाती है।

काम की जगहों पर लिंग के आधार पर भेदभाव भी गर्मी के संपर्क को प्रभावित करता है। एक रिसर्च से पता चलता है कि अनौपचारिक काम की जगहों पर साफ-सफाई की कमी महिलाओं को बहुत ज्यादा गर्मी के दौरान खास तौर पर परेशान करती है। कुछ महिलाएं गंदे टॉयलेट इस्तेमाल करने से बचने के लिए कम पानी पीती हैं, जिससे उनमें डिहाइड्रेशन और सेहत से जुड़ी और दूसरी समस्याएं उत्पन हो जाती हैं। ये छोटी-मोटी परेशानियां नहीं हैं। ये सब मिलकर महिलाओं के गर्मी के संपर्क में निरंतर इजाफा करती हैं।

बहुत ज्यादा गर्मी महिलाओं की सामाजिक दुनिया को बदल देती है। हीटवेव के दौरान कई उष्णकटिबंधीय जगहों पर औरतें घर के अंदर रहती हैं, जिससे उनके सामाजिक संपर्क कम हो जाते हैं। बांग्लादेश, कंबोडिया और नेपाल में तेज गर्मी को बाल विवाह में बढ़ोतरी से जोड़ा गया है, क्योंकि मुश्किल में फंसे परिवार पैसे का तनाव कम करने और घर का खर्च कम करने के लिए अपनी बेटियों को शादी के लिए मजबूर करते हैं।

एक अन्य अध्ययन के अनुसार दुनिया के कई हिस्सों में परिवार ऐसे घरों में रहते हैं जो गर्मी को अंदर रोककर रखते हैं, जहां बिजली की भरोसेमंद सुविधा नहीं है और साफपानी की उपलब्धता सीमित है। बहुत से लोग आज भी चिलचिलाती धूप में बाहर काम करते हैं। जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ रहा है, इस तरह के हालात सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर संकट पैदा कर रहे हैं।

'नेचर सस्टेनेबिलिटी' में छपी एक नई स्टडी में बताया गया है कि दुनिया में अरबों लोग 'कूलिंग पॉवर्टी' (ठंडक की कमी) का सामना कर रहे हैं। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि दो अरब से ज्यादा

लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसे वे कूलिंग पॉवर्टी कहते हैं। यानी वे खतरनाक गर्मी का सामना करते हैं और उनके पास ठंडक पाने के सुरक्षित या सस्ते तरीके नहीं होते। ये नतीजे ऐसे समय में आए हैं जब दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में इन गर्मियों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। इतनी ज्यादा गर्मी ये जरूरी सवाल खड़े करती है कि सबसे ज्यादा खतरे में कौन है और उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है। आमतौर पर लोग मान लेते हैं कि इन लोगों को बस एक एयर कंडीशनर की जरूरत है। शोधकर्ता इस सोच को बदलना चाहते हैं। यूरो-मेडिटेरेनियन सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज के वैज्ञानिक जियाकोमो फाल्चेटा ने कहा, कूलिंग पॉवर्टी का मतलब ऐसे हालात से है जहां लोगों को ताप सुरक्षा नहीं मिल पाती और इसकी वजह सिर्फ यह नहीं है कि उनके पास एयर कंडीशनर नहीं है।

वैसे भी, एयर कंडीशनर बांटने से कोई लाभ नहीं होगा। वे बहुत ज्यादा बिजली की खपत करते हैं और कमजोर पावर ग्रिड पर बोझ डालते हैं। हम इस संकट से निपटने के लिए सिर्फएयर कंडीशनर का सहारा नहीं ले सकते। गरीबी गर्मी के असर को और बढ़ा देती है। स्टडी से पता चलता है कि गर्मी गरीबी, खराब घरों और कमजोर सार्वजनिक सेवाओं के साथ मिलकर नुकसान पहुंचाती है। पहला खतरा तो घर ही है। कमजोर बनावट वाला घर आपको गर्मी से नहीं बचाताय बल्कि वह गर्मी को अंदर ही रोककर रखता है।

शहरों में रहने वाले लाखों गरीब लोग टिन या एस्बेस्टस की छतों के नीचे रहते हैं, जिससे घर के अंदर का तापमान बाहर की हवा के मुकाबले पांच डिग्री तक ज्यादा हो सकता है। जब बिजली बार-बार जाती है और पानी सुरक्षित नहीं होता, तो पर्याप्त पानी पीना और शरीर को ठंडा रखना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरा खतरा सेहत से जुड़ा है। जब भीषण गर्मी शरीर की सहनशक्ति से बाहर हो जाती है, तो जान बचाने के लिए अक्सर तुरंत मदद की जरूरत होती है। जिन देशों में क्लिनिक कम हैं या दूर हैं, वहां गर्मी से होने वाली बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। तीसरा खतरा काम से जुड़ा है। किसान, निर्माण कार्य करने वाले और सड़क किनारे सामान बेचने वाले लोग घंटों तक खुली धूप में काम करते हैं और वे किसी ठंडे कमरे में नहीं जा सकते। उनके शरीर को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह गर्मी ज्यादातर नमी वाली होती है, जिससे पसीना त्वचा को ठंडा नहीं कर पाता। इन मुश्किलों का असर सब पर एक जैसा नहीं होता।

महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और सबसे गरीब परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अक्सर यही लोग खराब घरों में रहते हैं। उन्हें स्वास्थ्य सेवा और जानकारी नहीं मिल पाती, और खुद को बचाने के लिए उनके पास कोई अतिरिक्त साधन नहीं होता। अगर समुदायों के पास गर्मी से निपटने के साधन हों, तो इसके असर को कम किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि आसान और कम खर्चीले उपाय भी कारगर होते हैं। छतों को सफेद रंगने से कमरे का तापमान कई डिग्री कम हो सकता है। पुआल और मिट्टी से सस्ता इंसुलेशन (तापमान रोकने वाली परत) बनाया जा सकता है। पेड़ लगाने, तालाबों और पार्कों को ठीक करने और निरूशुल्क पानी की सुविधा वाले सार्वजनिक शेल्टर खोलने जैसे उपायों से पूरे इलाके को बिना किसी एयर कंडीशनर के ठंडा रखने में मदद मिलती है।

निसंदेह, तेजी से गर्म होती दुनिया में ढालने के लिए सरकारों, संस्थाओं और लोगों को मिलकर कोशिश करनी पड़ेगी। छतों पर सफेद पेंट को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि सफेद पेंट सूरज की अधिकांश रोशनी को परावर्तित करके कमरों को ठंडा रखता है। सरकार को इसके लिए विशेष जन अभियान चलाना चाहिए। चूंकि गर्मी महिलाएं और पुरुषों को अलग-अलग ढंग से प्रभावित करती है, नीति-निर्धारकों को इस अंतर का भी ध्यान रखना पड़ेगा।

जिला अस्पताल में विवाद

माही की गूंज, मंदसौर।

जिला अस्पताल में एक विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें एक लेडी सुपरवाइजर पर मरीज के परिजन के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एक महिला अपने बेटे के लिए खाना लेकर अस्पताल पहुंची थी। इसी दौरान उसे अस्पताल परिसर में अंदर जाने से रोका गया, जिस पर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि रोकने को लेकर कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विवाद के दौरान लेडी सुपरवाइजर ने महिला को थप्पड़ जड़े और उसके साथ धक्का-मुक्की भी की। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन ने मामले की जानकारी मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो की भी जांच की जा रही है, ताकि घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि नियमों के अनुसार मरीजों के परिजनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाता है, लेकिन किसी भी स्थिति में हिंसा या दुर्व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। फिलहाल इस घटना को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

नारकोटिक्स विभाग ला रहा है खेती का डिजिटल अवतार

नीमच-मंदसौर।

अब अफीम की खेती में साइंस का तड़काश् लगने जा रहा है। अफीम के गढ़ में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का ऐलान किसानों को खेती के उन्नत वैज्ञानिक तरीकों से ,नीमच-मंदसौर में सजेगा श्हाईटेक अफीमश् का मेला! मालवा की धरती और अफीम के श्काले सोनेश् से जुड़ी सबसे बड़ी खबर! केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो अब अफीम उत्पादक किसानों की किस्मत चमकाने के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठाने जा रहा है। नीमच और मंदसौर जिलों में जल्द ही हाई-टेक और वैज्ञानिक खेती के महा-शिविर लगाए जा रहे हैं। अब वो पुराने दिन गए जब किसान सिर्फपारंपरिक तौर-तरीकों के भरोसे

रहते थे। अब अफीम की खेती में साइंस का तड़काश् लगने जा रहा है!

खत्म होगा नुकसान, बढ़ेगी अफीम की क्वालिटीरू वैज्ञानिक तरीके से चीरा लगाने और डोडा-चूरा की देखरेख की ऐसी तकनीकें सिखाई जाएंगी, जिससे अफीम की शुद्धता और पैदावार दोनों आसमान छू लेंगी।

इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग

किसानों को बताया जाएगा कि वैश्विक स्तर पर अफीम की मांग कैसी है और वैश्विक मानकों पर कैसे खरा उतरा जाए। विभाग के बड़े अधिकारी खुद चौपाल लगाकर किसानों के सारे कन्फ्यूजन दूर करेंगे। कब, कैसे और कितनी अफीम देनी है। इसकी पारदर्शी जानकारी सीधे किसानों तक पहुंचेगी। आधुनिक टूल्स और आधुनिक खाद-दवाइयों का लाइव डेमो दिया जाएगा ताकि मेहनत कम और मुनाफा डबल मिल सके।

जिला प्रशासन ने शासकीय भूमि को कराया अतिक्रमण मुक्त

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले में कलेक्टर अदिती गर्ग के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन ने मंगलवार को शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए तहसील गरोठ के ग्राम कुरलासी में लगभग 5 करोड़ रुपये बाजार मूल्य की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गरोठ राहुल चौहान ने बताया कि ग्राम कुरलासी में उद्योग विभाग को आवंटित शासकीय भूमि, सर्वे क्रमांक 888 एवं 889, कुल रकबा 6.16 हेक्टेयर पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। उक्त भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 5 करोड़ रुपये है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई राजस्व एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से शासकीय भूमि को सुरक्षित कर उसके नियोजित उपयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है।कार्यवाही के दौरान तहसीलदार अर्जुन भदौरिया, नायब तहसीलदार निगम, रघुनाथ मचार तथा पुलिस विभाग से थाना प्रभारी बलवीर यादव सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

मानव अधिकारों के संरक्षण और पेयजल पर प्राथमिकता

माही की गूंज, रतलाम।

मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह ने मंगलवार को रतलाम प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर मानव अधिकारों के संरक्षण तथा जनहित से जुड़े मामलों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा शासन और प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

बैठक में आयोग अध्यक्ष ने जिले में मानव अधिकार संबंधी प्रकरणों, पेयजल व्यवस्था और अन्य जनहित के मुद्दों की समीक्षा की। उन्होंने प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी वैशाली जैन तथा नगर निगम आयुक्त अनिल भाना से जिले में पेयजल आपूर्ति और दूषित जल की शिकायतों के संबंध

में जानकारी प्राप्त की।

अधिकारियों ने बताया कि जिले में पेयजल स्रोतों की नियमित जांच की जा रही है। जो हैंडपंप अथवा जलस्रोत पेयजल योग्य नहीं पाए जाते, उन्हें रेड मार्किंग कर चिन्हित किया जाता है तथा सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है।

डॉ. सिंह ने लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उनके समयबद्ध निराकरण पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों की रक्षा केवल आयोग का दायित्व नहीं, बल्कि शासन, प्रशासन और समाज की साझा जिम्मेदारी है। नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकार उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन से जुड़े मामलों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए तथा पेयजल, राजस्व और पुलिस प्रकरणों से संबंधित लंबित मामलों में प्रभावी कार्रवाई कर आयोग को अवगत कराया जाए। आयोग अध्यक्ष ने विश्वास व्यक्त किया कि जिला प्रशासन मानव अधिकारों के संरक्षण और जनकल्याण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाएगा।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल, एसडीएम आर्ची हरित तथा जिला परिवहन अधिकारी जगदीश बिल्लौरे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

रिटायर्ड शिक्षिका से सोने-चांदी के जेवर और नकदी से भरा बैग लेकर फरार

माही की गूंज, रतलाम।

शहर से ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शातिर ठगों ने एक रिटायर्ड शिक्षिका को बातों में उलझाकर उनके सोने के जेवर, नकदी और मोबाइल से भरा बैग लेकर फरार हो गए। इस पूरी वारदात ने इलाके में दहशत और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है।

यह घटना 7 जून की शाम की बताई जा रही है, जबकि इसका सीसीटीवी फुटेज सोमवार रात सामने आया, जिसके बाद मामला और अधिक चर्चा में आ गया। फुटेज में ठगों की चालाकी और वारदात को अंजाम देने का तरीका साफ तौर पर देखा जा सकता है।

बातचीत के बहाने बनाया निशाना

जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने पहले पीड़िता को बातचीत में उलझाया और धीरे-धीरे उनका भरोसा जीत लिया। इसके बाद मौका पाकर उन्होंने उनके बैग पर हाथ साफकर दिया, जिसमें सोने के जेवर, नकदी और मोबाइल फोन रखा हुआ था।

सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात

वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें ठगों की हरकतें साफदिखाई दे रही हैं। पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है।

पुलिस जांच में जुटी

घटना सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

स्थानीय लोगों में दहशत

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल है। लोगों ने मांग की है कि बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। फिलहाल पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और ठगों की तलाश तेज कर दी गई है।

स्कूल का बाबू 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

माही की गूंज, रतलाम।

जिले में उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को एक सरकारी स्कूल के बाबू को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत वह सेवानिवृत्त कर्मचारी के दस्तावेजों को जारी करने के बदले मांग रहा था। लोकायुक्त एसपी आनंद कुमार यादव ने बताया कि आवेदक लक्ष्मीनारायण लोट, सेवानिवृत्त उच्च माध्यमिक शिक्षक शा उ.मा. वि हाटपिपल्या ब्लॉक जावरा, जिला रतलाम, निवासी- विश्रामगृह के पीछे, जावरा, जिला रतलाम ने समक्ष में शिकायत की थी कि आरोपी अनिल वर्मा, सहायक ग्रेड-2 (बाबू) संकुल केन्द्र शा. क. उ.मा. वि कमला नेहरू जावरा जिला रतलाम, उसकी सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र व पीपीओ जारी करवाने के एवज में रिश्वत राशि 10 हजार रूपये मांग रहा है। शिकायत की पुष्टि होने पर मंगलवार को आवेदक लक्ष्मीनारायण लोट से अनावेदक अनिल वर्मा सहायक ग्रेड -2 (बाबू) को 10 हजार रूपये लेते ट्रेप किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी ने रिश्वत राशि अपने हाथ में लेकर अपनी टेबल की दराज के ऊपर रखे रजिस्टर के नीचे रख लिए थे, जो उक्त रिश्वत राशि टेबल की दराज के ऊपर रखे रजिस्टर के नीचे से बरामद की गई। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कीधारा-7 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। टीम द्वारा आगे की कार्रवाई जारी रही है। ट्रैप दल में डीएसपी दिनेशचंद्र पटेल, निरीक्षक हीना डावर, प्र.आर. हितेश ललावत, आर. उमेश जाटव, आर. श्याम शर्मा, आर. नीरज राठौर, आर. संदीप कदम शामिल थे।

सरकारी कर्मचारी के घर से 1.45 करोड़ रुपये हुए गायब

माही की गूंज, शुजालपुर।

घर में पेटी के अंदर बक्से में रखे एक करोड़ 45 लाख रुपये रहस्मय ढंग से गायब होने का मामला सामने आया है। घटना शुजालपुर के मोती मोहल्ला फ्रीगंज निवासी कन्हैयालाल वर्मा के यहां हुई। उन्होंने अपनी बहू पर ही रुपये गायब करने की शंका जाहिर कर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

पुलिस को दी जानकारी में कन्हैयालाल ने बताया कि वह कन्या शाला विद्यालय शुजालपुर सिटी में सहायक ग्रेड-तीन (लिपिक) के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने ग्राम जेठड़ा स्थित जमीन एक वर्ष पहले दो करोड़ 79 लाख रुपए में बेची थी। एक करोड़ रुपए से भोपाल और सीहोर में जमीन खरीद ली थी। शेष राशि एक करोड़ 79 लाख रुपए घर में एक पेटी के अंदर बक्से में रखे थे। उनका इकलौता पुत्र सीहोर में व्यापार करता है। घर में बहू व उसके बच्चे भी रहते हैं।

चाबी बहू को सौंपकर गए थे

20 दिसंबर 2025 को वह पत्नी सुशीला बाई के साथ नाती के जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भोपाल गए थे। घर पर बहू विनिता और उनके तीन बच्चे थे। उन्होंने पेटी और बक्से की चाबी बहू को सौंपी और बताया था कि रुपये रखे हैं। 21 दिसंबर 2025 को वह लौटे बहू से चाबी वापस लेकर पेटी और बक्सा खोला। उन्होंने राशि निकालकर देखी तो उसमें एक करोड़ 79 लाख रुपए के स्थान पर केवल 34 लाख रुपए ही मिले। इस तरह कुल राशी में से एक करोड़ 45 लाख रुपए गायब मिले। उन्होंने लंबे समय तक बहू को समझाया बावजूद रुपयों का पता नही चला। जिस पर उन्होंने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस कर रही मामले की जांच

फरियादी कन्हैया लाल वर्मा ने घर पर पेटी बक्से में राशी रखी थी, चाबी बहू को देकर अन्य शहर गए थे। आकर देखा तो कुल राशी में से एक करोड़ 45 लाख रुपये कम पाए गए हैं। जिस पर उन्होंने बहू पर शंका जाहिर की है। केस दर्ज कर मामले की जांच कर रहे हैं। बहू के बयान लिये जाएंगे।

-एसके यादव
थाना टीआई शुजालपुर मंडी

अस्पताल में गार्ड मरीजों को चढ़ा रहा था ड्रिप

सिंगरौली।

मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का चितरंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों किसी उपलब्धि की वजह से नहीं, बल्कि एक वायरल वीडियो की वजह से चर्चा में है। वीडियो में एक शख्स मरीजों को ड्रिप चढ़ाता दिखाई दे रहा है। आरोप है कि वह अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड है। यानी जिसकी जिम्मेदारी अस्पताल की सुरक्षा देखना है, वह मरीजों के इलाज से जुड़ा काम करता नजर आ रहा है।

अब अगर यह आरोप सही है, तो सवाल छोटा नहीं है. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भी सामने आया है। उनका कहना है कि चितरंगी अस्पताल में यह कोई नई बात नहीं है। यहां पहले भी वार्ड बॉय द्वारा इंजेक्शन लगाने और ड्रिप चढ़ाने जैसी घटनाओं के वीडियो सामने आ चुके हैं। यानी आरोप यह है कि अस्पताल में इलाज का काम प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ नहीं, बल्कि दूसरे कर्मचारी संभाल रहे हैं और अगर ऐसा

है, तो फिर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफआखिर कर क्या रहे हैं? वीडियो बनाने वाले राकेश मौर्य का कहना है कि अस्पताल की व्यवस्था लंबे समय से सवालों के घेरे में है। उनके मुताबिक, कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां मरीजों की देखभाल और इलाज से जुड़े काम गैर-प्रशिक्षित लोग करते दिखाई दिए हैं। वीडियो में भी इसी तरह का दृश्य कैद हुआ, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही लोगों का ध्यान खींच लिया।

सबसे बड़ा सवाल- दोपहर 2 बजे स्टाफकहां था?

स्थानीय लोगों के मुताबिक, घटना दोपहर करीब 2 बजे की है। यह वह समय होता है जब अस्पताल पूरी तरह सक्रिय रहता है। ऐसे में सवाल है कि अगर एक सुरक्षा गार्ड ड्रिप लगा रहा था, तो उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मी कहां थे? क्या वे अस्पताल में मौजूद नहीं थे? या फिर मौजूद थे और जिम्मेदारी किसी और के हवाले कर दी गई थी?

सोशल मीडिया पर मामला तूल पकड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। सीएमएचओ सिंगरौली पुष्पराज सिंह का कहना है कि एक वीडियो संज्ञान में आया है। चितरंगी ब्लॉक मेडिकल आफिसर को पत्र भेजकर जानकारी की जा रही है, साथ ही नर्सिंग स्टाफ कहां था, सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने वाली संस्था को सैडमैप को भी नोटिस जारी किया है। फिलहाल जांच शुरू हो चुकी है और स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार लोगों की पहचान करने की बात कह रहा है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्योंकि अगर अस्पताल में मरीजों को ड्रिप चढ़ाने का काम सुरक्षा गार्ड कर रहे हैं, तो यह सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का एक्स-रे है, जो कागजों में तो ठीक दिखती है, लेकिन जमीन पर अक्सर बीमार नजर आती है।

चोर समझकर ग्रामीणों ने पुलिस दल से की मारपीट, चार हिरासत में

माही की गूंज, खंडवा

बोरगांव बुजुर्ग चौकी क्षेत्र के ग्राम कुमठी में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट की स्थिति निर्मित हो गई। घटना के बाद पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि आदिवासी समाज के लोगों ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है।

जानकारी के अनुसार पुलिस दल गांव में कच्ची शराब के खिलाफकार्रवाई के लिए पहुंचा था। ग्रामीणों का आरोप है कि मौके पर मौजूद एक सहायक उपनिरीक्षक और एक आरक्षक वर्दी में नहीं थे, बल्कि सामान्य कपड़ों में थे। उनके साथ कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे। ग्रामीणों का कहना है कि देर रात पहुंचे लोगों की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने के कारण वे उन्हें पुलिसकर्मी नहीं पहचान सके।

बताया जाता है कि रात करीब 12 बजे ग्रामीणों ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की। संदेह होने पर कुछ लोगों ने डायल-112 और पुलिस को सूचना देने की बात कही। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने पहचान बताने के लिए कहा, लेकिन इसी दौरान विवाद बढ़ गया।

ग्रामीण पक्ष ने आरोप लगाया है कि शिकायत करने और पुलिस बुलाने की बात पर कुछ पुलिसकर्मी नाराज हो गए तथा एक युवक के साथ मारपीट की गई, जिससे उसके सिर में चोट आई। घटना के बाद गांव में आक्रोश फैल गया और विवाद ने उग्र रूप ले लिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसके बाद दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की और मारपीट हुई। विवाद के दौरान लाठी-डंडे चलने की बात भी सामने आई है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। वहीं आदिवासी समाज के लोगों का आरोप है कि उनकी शिकायत में अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया, जबकि उनके समाज के लोगों के खिलाफनामजद प्रकरण दर्ज किया गया है।

आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि भागीरथ पिता जगत, गणेश पिता कालू, गणेश पिता जगन, जगन पिता चवरसिंह और छोटू पिता राम के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। समाज के लोगों का आरोप है कि उनकी बात को गंभीरता से नहीं सुना गया और एकतरफा कार्रवाई की गई। समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि वे इस मामले को लेकर बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराएंगे। उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा।

घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फिलहाल कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोनों पक्षों के बयान तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

खराब सड़क बनी हादसे का कारण, किसान गंभीर रूप से घायल

माही की गूंज, बड़वानी

जिले के आंवली बसाहट गांव में जर्जर ग्रामीण सड़क एक बार फिर दुर्घटना का कारण बन गई। बुधवार सुबह किसान रामपाल पुत्र जगदीश राजपूत खेत से मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान गांव के मार्ग पर उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे वे सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा घायल रामपाल को उपचार के लिए अंजड़ सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल अधिकारी डॉ. रोहित मंडलोई ने उनकी हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल बड़वानी रेफर कर दिया। वर्तमान में उनका उपचार जिला अस्पताल में जारी है।

आंवली बसाहट निवासी रामसिंह सिसौदिया ने बताया कि गांव का मार्ग लंबे समय से खराब स्थिति में है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ग्रामीण कई बार संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक सड़क सुधार का कार्य शुरू नहीं किया गया है। रामपाल राजपूत के घायल होने की घटना के बाद ग्रामीणों में नाराजगी देखी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो भविष्य में भी ऐसे हादसे होते रहेंगे। उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द मार्ग की मरम्मत करवाने की मांग की है।

तीन माह से मानदेय नहीं मिलने पर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन

माही की गूंज, बड़वानी

बड़वानी जिले में आशा कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगिनी महासंघ ने अपनी लंबित मांगों और समस्याओं के निराकरण को लेकर बुधवार दोपहर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। महासंघ की ओर से मुख्यमंत्री और कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार बाबू सिंह निनामा को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगी।

महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष दिपाली शर्मा ने बताया कि 6 सितंबर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा आशा कार्यकर्ताओं और पर्यवेक्षकों के महासम्मेलन में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थीं, लेकिन सरकार बदले जाने और लंबा समय बीत जाने के बाद भी उन घोषणाओं का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष मानदेय में एक हजार रुपए की वृद्धि का वादा भी अब तक पूरा नहीं किया गया है।

महासंघ ने ज्ञापन में बताया कि आशा कार्यकर्ताओं को पिछले तीन माह से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे उनके परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। अधिकांश कार्यकर्ता आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं और नियमित भुगतान नहीं होने से उन्हें गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से अलग-अलग राशि मिलने के कारण भ्रम की स्थिति बनी रहती है। कम पढ़ी-लिखी कार्यकर्ताओं को यह समझने में कठिनाई होती है कि किस मद की राशि प्राप्त हुई है और कौन-सी राशि लंबित है। शिकायत करने पर अधिकारियों द्वारा बजट की कमी या सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याओं का हवाला दिया जाता है।

महासंघ ने मांग की है कि केंद्र, राज्य और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राशि को मिलाकर पूर्व की भांति एकमुश्त भुगतान की व्यवस्था लागू की जाए। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए प्रतिमाह निर्धारित करने तथा सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मांग भी उठाई गई है।

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

माही की गूंज, धामनोद।

पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई धामनोद पुलिस द्वारा गठित एक विशेष दल ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर की है।

मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता अपने परिजनों के साथ धामनोद थाने पहुंची। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीती 15 मई को एक युवक उसे बहला-फुसलाकर खरगोन ले गया था, जहां उसने किराए के कमरे में उसे पत्नी बनाकर रखा और उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। किसी तरह वहां से छूटकर पीड़िता 9 जून को अपने घर पहुंची और आपबीती सुनाई।

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तत्परता दिखाते हुए भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस दल ने घेराबंदी कर आरोपी नवल उर्फलालू (20 वर्ष), पिता गणेश डुडवे को हिरासत में लिया। आरोपी खरगोन जिले के कसरावद क्षेत्र के बालसमुद गांव का रहने वाला है। कड़ाई से की गई पूछताछ में जुर्म कबूलने और पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

दिव्यांग क्रिकेटर का इंडिया-ए टीम में चयन, गांव में खुशी का माहौल

माही की गूंज, सेंधवा

सेंधवा ब्लॉक के मोरदड़ गांव के 26 वर्षीय दिव्यांग क्रिकेटर लोकेंद्र आर्य का चयन दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया की इंडिया-ए टीम में हुआ है। वे 13 से 15 जून तक हरियाणा के यमुनानगर में आयोजित केसरी दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट-2026 में इंडिया-ए टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे।

बाएं पैर से दिव्यांग और दाएं हाथ के बल्लेबाज लोकेंद्र वर्तमान में दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन मध्यप्रदेश की सतपुड़ा संभागीय ग्रामीण टीम के कप्तान हैं। बचपन में शारीरिक कमजोरी को लेकर लोगों के ताने और उपहास का सामना करने वाले लोकेंद्र ने इन्हीं चुनौतियों को अपनी ताकत बनाकर सफलता की नई मिसाल पेश की है।

लोकेंद्र ने बताया कि पोलियो से प्रभावित होने के कारण उनका बचपन संघर्षों से भरा रहा। वर्ष 2006 में उनके पिता उन्हें झाकर स्थित पद्मश्री कांता विकलांग सेवा ट्रस्ट आश्रम में छोड़ गए थे। वहां उन्होंने लगातार 12 वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त की। इसी दौरान दिव्यांग साथियों के साथ क्रिकेट खेलते हुए उनके मन में इस खेल के प्रति गहरी रुचि और जुनून पैदा हुआ।

आश्रम से बाहर आने के बाद भी उन्होंने क्रिकेट से अपना जुड़ाव बनाए रखा। वर्ष 2021 में उन्हें दिव्यांग क्रिकेट के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद उनकी मुलाकात ब्रजेश द्विवेदी से हुई, जिन्होंने उनके क्रिकेट सफर को नई दिशा दी। उन्हें दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन मध्यप्रदेश से जुड़ने का अवसर मिला और सतपुड़ा संभागीय टीम का गठन हुआ।

लोकेंद्र के अनुसार गांव में कई लोग उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि दिव्यांग व्यक्ति क्रिकेट में सफल नहीं हो सकता। कई लोगों ने उन्हें खेल छोड़कर पढ़ाई और नौकरी पर ध्यान देने की सलाह भी दी, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया और वर्ष 2021 से चमड़े की गेंद से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया।

शुरुआती दिनों में क्रिकेट किट और मैदान जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। ऐसे में साथियों ने आपस में सहयोग राशि एकत्र कर दो क्रिकेट किट खरीदीं। अभ्यास के लिए वे सेंधवा से लगभग 20 किलोमीटर दूर निवाली खेल परिसर पहुंचते थे, जहां अनुमति लेकर प्रत्येक शनिवार और रविवार को घंटों अभ्यास करते थे।

लोकेंद्र के इंडिया-ए टीम में चयन की खबर मिलते ही मोरदड़ गांव में खुशी का माहौल है। मित्र, रिश्तेदार और ग्रामीण उनके घर पहुंचकर शुभकामनाएं दे रहे हैं तथा उनकी उपलब्धि पर गर्व व्यक्त कर रहे हैं।

सरकारी रिकॉर्ड से गायब हुई किसानों की जमीन, तहसील घेराव जारी

माही की गूंज, खरगोन

खरगोन जिले के भगवानपुरा तहसील अंतर्गत दगड़खेड़ी गांव के ग्रामीणों ने अपनी पैतृक भूमि को सरकारी रिकॉर्ड में शासकीय भूमि दर्शाए जाने के विरोध में तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन जारी रखा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वे कई पीढ़ियों से संबंधित भूमि पर खेती कर रहे हैं तथा उनके पास पावती, पट्टे और अन्य राजस्व दस्तावेज मौजूद हैं, इसके बावजूद उनकी जमीन को सरकारी भूमि बताकर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी की जा रही है।

सोमवार से तहसील परिसर का घेराव कर रहे ग्रामीणों ने रात भी वहीं बिताई और भोजन की व्यवस्था भी परिसर में ही की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। मंगलवार को भी धरना जारी रहा और ग्रामीणों ने भूमि अभिलेखों में सुधार होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी।

जागृत आदिवासी दलित संगठन के बलिराम सोलंकी और शिवराम कनासे ने बताया कि वर्ष 2022 से मुख्यमंत्री, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा तहसील कार्यालय में लगातार आवेदन देकर भूमि अभिलेखों में सुधार की मांग की जा रही है। उनका आरोप है कि लगभग 250 किसानों की करीब 500 एकड़ भूमि को शासकीय भूमि दर्शाकर वहां औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना बनाई गई है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने दावा किया कि संबंधित भूमि किसानों के नाम दर्ज रही है और इसके पावती-पट्टे भी उपलब्ध हैं। उनका कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड से किसानों के नाम हट जाने के कारण वे विभिन्न किसान कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित हो रहे हैं।

मामले को लेकर ग्रामीणों ने पूर्व में अनुसूचित जनजाति आयोग के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतरसिंह आर्य को भी अवगत कराया था। ग्रामीणों का कहना है कि यदि राजस्व रिकॉर्ड में सुधार कर उनकी भूमि पुनः दर्ज नहीं की गई तो वे कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर बड़ा आंदोलन करेंगे। तहसीलदार संजय चौहान ने बताया कि किसानों की समस्या से जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। वहीं मंगलवार देर शाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सत्येंद्र बैरवा मामले की जानकारी लेने भगवानपुरा के लिए रवाना हुए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण की स्थिति समझने और आवश्यक जांच के बाद ही इस संबंध में स्पष्ट जानकारी दी जा सकेगी।

महिला किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए किया प्रेरित

माही की गूंज, आलीराजपुर।

देशभर में चल रहे प्राकृतिक खेती अभियान के बीच आलीराजपुर की सांसद श्रीमती अनिता नागर सिंह चौहान ने एक प्रेरणादायक पहल करते हुए स्वयं प्रशिक्षु छात्रा बनकर ग्रामीण महिला किसानों के साथ प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने प्राकृतिक खेती में उपयोग होने वाली जैविक खाद एवं प्राकृतिक कीटनाशकों के निर्माण और उपयोग की विधियों को समझने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र आलीराजपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता की।

सांसद श्रीमती चौहान के अनुरोध पर कृषि विज्ञान केंद्र, आलीराजपुर द्वारा 6 से 8 जून तक तीन दिवसीय प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए केवीके के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. राकेश यादव ने बताया कि प्रशिक्षण में जिले की 30 ग्रामीण महिला किसानों ने भाग लिया और प्राकृतिक खेती की विभिन्न तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

प्रशिक्षण के दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. बी.एल. प्रजापति, डॉ. सुभाष रावत, डॉ. एम.के. गुप्ता, डॉ. मुकेश बेनल तथा डॉ. सुदीप तोमर ने प्रतिभागियों को प्राकृतिक खेती की उपयोगिता, जैविक खाद एवं प्राकृतिक कीटनाशकों के निर्माण की विधियों की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही सभी प्रतिभागियों को केंद्र में विशेष रूप से विकसित प्राकृतिक खेती परिसर का भ्रमण भी कराया गया। कार्यक्रम में केंचुआ खाद, जीवामृत, बीजामृत, निमास्त्र तथा पाँच पत्ती काढ़ा जैसे प्राकृतिक उत्पादों के निर्माण, उपयोग एवं खेती में उनके लाभों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर डॉ. राकेश यादव ने सांसद द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देते हुए बताया कि प्राकृतिक खेती पर्यावरण संरक्षण, भूमि स्वास्थ्य सुधार तथा किसानों एवं उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है।

सांसद श्रीमती अनिता नागर सिंह चौहान ने कहा कि खेती में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से भूमि की उर्वरता प्रभावित हो रही है, मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है। इसके साथ ही कृषि लागत में वृद्धि होने से किसानों का लाभ भी कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती इन सभी चुनौतियों का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करती है। उन्होंने उपस्थित महिला किसानों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्राकृतिक खेती संबंधी सोच एवं संकल्प से अवगत कराया तथा स्वयं प्राकृतिक खेती अपनाने के साथ सभी किसानों को भी इसे अपनाने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम के दौरान डीएससी के जितेंद्र गोयल एवं मनीष गिरधानी ने पोषण वाटिका एवं बीआरसी से संबंधित जानकारी साझा करते हुए जिले में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। उक्त जानकारी केवीके के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ राकेश यादव द्वारा दी गई।

कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने पेयजल व्यवस्थाओं की समीक्षा की

माही की गूंज, आलीराजपुर।

जिले में पेयजल व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर द्वारा प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के दौरान संबंधित विभागों को पेयजल संबंधी समस्याओं का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाते हैं। साथ ही पीएचई अधिकारी के माध्यम से प्रतिदिन पेयजल समस्याओं के समाधान की जानकारी भी प्राप्त की जाती है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी सुखराम मेडा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जानकारी देते हुए बताया कि 9 जून 2026 को जिले में कुल 81 हैंडपंपों का संधारण कार्य किया गया। इस दौरान 229 मीटर राइजर पाइप बदले गए। इसके अतिरिक्त इन 81 हैंडपंपों के संधारण कार्य के साथ इनका तथा 17 कुओं का क्लोरीनेशन का कार्य किया गया। विकासखंडवार किए गए कार्यों में आलीराजपुर विकासखंड में 17 हैंडपंपों का संधारण, 81 मीटर राइजर पाइप प्रतिस्थापन, 17 हैंडपंप एवं 4 कुओं का क्लोरीनेशन किया गया। जोबट विकासखंड में 12 हैंडपंपों का संधारण, 21 मीटर राइजर पाइप प्रतिस्थापन, 12 हैंडपंप एवं 3 कुओं का क्लोरीनेशन किया गया। सोंडवा विकासखंड में 18 हैंडपंप का संधारण कार्य एवं क्लोरिनेशन और 2 कुओं का क्लोरिनेशन किया गया। उदयगढ़ विकासखंड में 11 हैंडपंपों का संधारण, 19 मीटर राइजर पाइप प्रतिस्थापन, 11 हैंडपंप एवं 2 कुओं का क्लोरीनेशन किया गया। वहीं चन्द्रशेखर आजाद नगर विकासखंड में 10 हैंडपंपों का संधारण, 27 मीटर राइजर पाइप प्रतिस्थापन, 10 हैंडपंप एवं 2 कुओं का क्लोरीनेशन किया गया। कट्ठीवाड़ा में 13 हैंडपंप का संधारण कर क्लोरिनेशन एवं 57 राइजर पाइप प्रतिस्थापन और 4 कुओं का क्लोरिनेशन किया गया। आलीराजपुर विकासखंड में बेगडी जमरा फलिया, लक्ष्मणी पटेल फलिया,जोबट विकासखंड में किला जोबट काकरिया फलिया, छोटी खट्टाली में बारिया फलिया, चांदपुर में तीन ताड़ फलिया, सोंडवा विकासखंड अंतर्गत भोरदिया जाम फलिया, गुलवट नरगावा फलिया, वावी कोटवाल फलिया,भरवाडी फलिया, धोरट-बस स्टैंड फलिया , उमराली में स्कूल फलिया सहित अन्य स्थलों पर हैंडपंप संधारण एवं कुओं के क्लोरिनेशन का कार्य किया गया।

कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जिले में पेयजल आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती संघमित्रा गौतम, अपर कलेक्टर सोहन कनास, सभी अनुभागों के अनुविभागीय अधिकारी, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

माण्डू एवं धरमपुरी विकास परियोजनाओं का किया निरीक्षण

माही की गूंज, धार।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी (एमपीयूडीसी) के अतिरिक्त प्रबंध संचालक दिव्यांक सिंह ने मंगलवार पर्यटन नगरी माण्डू और धरमपुरी में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं का जमीनी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को परखने के साथ-साथ अधिकारियों को समय-सीमा में काम पूरा करने के कड़े निर्देश दिए। माण्डू जल प्रदाय परियोजना की समीक्षा और पौधरोपण अतिरिक्त प्रबंध संचालक दिव्यांक सिंह ने माण्डू में एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से संचालित जल प्रदाय परियोजना के सभी प्रमुख घटकों का सूक्ष्म अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने ओव्हरहेड टैंक (ओएचटी) और जलशोधन संयंत्र (डब्लूटीपी) की कार्यप्रणाली को बारीकी से देखा। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सिंह ने ओएचटी परिसर में पौधरोपण भी किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने नगर परिषद अध्यक्ष, पार्षदों एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ जल प्रदाय व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अत्यंत उत्साहजनक जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस परियोजना के प्रभावी और कुशल संचालन से नगर निकाय को प्रतिमाह लगभग 3 से 4 लाख रुपये की वित्तीय बचत हो रही है। इसके साथ ही, सिंह ने गीता भवन एवं पार्किंग स्थल के प्रस्तावित स्थलों का भी जायजा लिया और इस संबंध में पर्यटन विभाग के अधिकारियों से आवश्यक समन्वय हेतु चर्चा की।

धरमपुरी सीवरेज परियोजना का जायजा

इसके पश्चात, अतिरिक्त प्रबंध संचालक दिव्यांक सिंह ने विश्व बैंक द्वारा सहायतित धरमपुरी सीवरेज परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मलजल शोधन संयंत्र (एसटीपी) का दौरा कर वहां शोधित जल के प्रायोगिक परीक्षण की जानकारी प्राप्त की और शोधित जल के पुनः उपयोग की प्रक्रिया का लाइव अवलोकन किया। क्षेत्र का दौरा करते हुए उन्होंने ब्रह्मपुरी क्षेत्र में निर्माणाधीन इंटरमीडिएट पम्प स्टेशन के सिविल कार्य की गति पर असंतोष जताते हुए इसे तत्काल तेज करने और समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इस महत्वपूर्ण निरीक्षण और समीक्षा कार्यक्रम के दौरान मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी के प्रमुख अभियंता आनंद सिंह, उप परियोजना संचालक (प्रशासन) राजीव रंजन पाण्डेय, परियोजना प्रबंधक डी.आर. लोधी, उप परियोजना प्रबंधक लालचंद कुरेठिया सहित स्थानीय प्रशासन और परियोजना से जुड़े तमाम वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी उपस्थित रहे।

उज्जैन बनेगा नो नॉनवेज जोन!

माही की गुनु, उज्जैन।

मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी माने जाने वाले उज्जैन में अब शराब के बाद मांस-मटन और मछली की दुकानों पर भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। बुधवार को होने वाली नगर निगम एमआईसी बैठक में ऐसा प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब इस पर मुहर लगते ही सभी मांस, मटन और मछली की दुकानों को नगरीय सीमा से बाहर शिफ्ट किया जाएगा।

लंबे समय से चली आ रही मांग-दरअसल, विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के साथ ही कई प्राचीन मंदिर होने से काफी समय से शहर में मांस मछली की दुकान बंद करने की मांग की जा रही हैं। 1 अप्रैल 2025 से उज्जैन सहित प्रदेश के कई धार्मिक शहरों में शराबबंदी लागू करने के बाद फिर शहर में नॉनवेज दुकानों को बंद करने की मांग होने लगी थी। इसी बीच हाल ही में वाराणसी में मांस-मटन और मछली की दुकानों को शहर से बाहर करने के फैसले के बाद अब नगर निगम इस की पहल शुरू कर दी। बता दें कि महाकाल मंदिर मार्ग तोपखाना, बेगमबाग में नॉनवेज की कई दुकानें होने से श्रद्धालुओं को परेशानी होती हैं।

शराब बंदी तो नॉनवेज क्यों नहीं?-महापौर मुकेश टटवाल ने कहा कि यह एक पवित्र धार्मिक नगरी है. जब यहां शराबबंदी लागू हो सकती है, तो मांस-मटन और मछली की दुकानें भी शहरी सीमा से बाहर होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि नगर निगम कमिश्नर को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसे कल एमआईसी बैठक में रखा जाएगा। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो आने वाले समय में उज्जैन नगर निगम सीमा के भीतर नॉनवेज की दुकानों का संचालन पूरी तरह बंद हो सकता है।

कृषि आदान विक्रेता संघ की वार्षिक साधारण सभाएं संपन्न

माही की गूंज, उज्जैन।

मध्यप्रदेश कृषि आदान विक्रेता संघ की प्रांतीय एवं उज्जैन जिला स्तरीय वार्षिक साधारण सभाएं उज्जैन में संपन्न हुईं। प्रदेश के 40 जिलों के पदाधिकारियों एवं उज्जैन जिले के 350 से अधिक कृषि आदान विक्रेताओं ने भाग लेकर व्यापारिक समस्याओं, संगठन विस्तार तथा कृषि आदान व्यवसाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक संभाग में संभागीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संगठन मंत्री एवं प्रचार मंत्री की टीम गठित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही सदस्यता अभियान को जारी रखने तथा जिन जिलों में सदस्यता अधूरी है वहां इसे गति देने पर सहमति बनी। व्यापारियों ने उर्वरक व्यवसाय में ई-टोकन व्यवस्था से आ रही समस्याओं को शासन स्तर पर उठाने का निर्णय भी लिया। प्रदेश अध्यक्ष मानसिंह राजपूत ने कृषि आदानों के ऑनलाइन व्यापार को लेकर व्यापारियों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए अधिकृत स्रोतों से ही माल खरीदने और बिल पर लॉट एवं बैच नंबर अंकित कराने पर जोर दिया। प्रदेश सचिव संजय रघुवंशी ने आगामी सीड एक्ट एवं पेस्टिसाइड बिल के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक को प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण दुबे, उज्जैन जिला अध्यक्ष लेखराज खत्री, जिला उपाध्यक्ष जवाहर जैन सहित विनोद जैन (खरगोन), रमेश गर्ग (रतलाम), शैलेंद्र बघेल (रीवा), प्रकाश जैन (बैतूल), आनंद कपूर (जबलपुर), अनुराग जैन (सागर), मोहन आर्य (आगर मालवा), राकेश जैन (मंदसौर), आशीष भंसाली (खंडवा), नरेश पहाड़िया (धार), शफ्फ़त भाई (अलीराजपुर), राजीव पीतलिया एवं दीपक चौरसिया (विदिशा), सुनील राठी (सीहोर), बालकृष्ण पाटिल (हरदा), प्रणीत समैया (सिलवानी), प्रवीण रघुवंशी (नर्मदापुरम) तथा उदय पटेल (बकतरा) ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन संजय रघुवंशी एवं आभार प्रदर्शन लाखन सिंह केलवा ने किया।

औद्योगिक क्षेत्र में गूंजा योग का संदेश

माही की गूंज, धार।

औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने और उनके बेहतर स्वास्थ्य के उद्देश्य से आज धार जिले के हातोद औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्अमृत पेपर्स प्राइवेट लिमिटेडश् के परिसर में एक विशाल एक दिवसीय योग शिविर एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह गरिमामयी आयोजन श्रम विभाग, धार के तत्वाधान और आयुष विभाग के तकनीकी सहयोग से संपन्न हुआ।अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल पर हुआ अभ्यासआगामी 21 जून को मनाए जाने वाले श्अंतरराष्ट्रीय योग दिवसश् को दृष्टिगत रखते हुए, आयुष विभाग धार से विशेष रूप से आमंत्रित योग प्रशिक्षकों ने शिविर की कमान संभाली। प्रशिक्षकों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य योग प्रोटोकॉल के अनुसार उपस्थित सभी अधिकारी-कर्मचारियों को क्रमबद्ध तरीके से योगाभ्यास कराया। शिविर की शुरुआत प्रार्थना से हुई, जिसके बाद ग्रीवा चालन, स्कंध चक्र जैसी शिथिलीकरण क्रियाएं कराई गईं। इसके पश्चात ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, वज्रासन, शशांकासन और भुजंगासन जैसे महत्वपूर्ण आसनों का अभ्यास कराया गया। सत्र के अंतिम चरण में भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति और ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाने के गुर सिखाए गए।कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन और सकारात्मकता पर जोरशिविर को संबोधित करते हुए मुख्य योग प्रशिक्षक ने कहा कि, ष्औद्योगिक इकाइयों में शिफ्ट ड्यूटी और काम के दबाव के कारण श्रमिक अनजाने में मानसिक तनाव और थकान का शिकार हो जाते हैं। प्रतिदिन मात्र 20 से 30 मिनट का योग न केवल उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी बीमारियों से बचाता है, बल्कि कार्यस्थल पर कार्यक्षमता और सकारात्मक ऊर्जा को भी दोगुना कर देता है।ष्प्रबंधन और श्रमिक वर्ग की अनुकरणीय सहभागिताइस अवसर पर अमृत पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड की मानव संसाधन टीम, प्रशासनिक अधिकारी, सुपरवाइजर्स सहित बड़ी संख्या में प्लांट के श्रमिकगण उपस्थित रहे। अधिकारियों से लेकर सुरक्षाकर्मियों और श्रमिकों तक ने एक साथ एक ही जाजम पर बैठकर योगाभ्यास किया, जो कार्यस्थल पर समानता और सद्भाव का एक अनूठा उदाहरण था।

कंपनी प्रबंधन ने श्रम विभाग की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि स्वस्थ श्रमिक ही देश के औद्योगिक विकास की रीढ़ हैं। प्रबंधन ने आश्वस्त किया कि वे भविष्य में भी श्रम विभाग के समन्वय से ऐसे स्वास्थ्य जांच और योग शिविरों का आयोजन निरंतर अंतराल पर करते रहेंगे। शिविर के समापन पर कई श्रमिकों ने अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि दैनिक भागदौड़ के बीच इस तरह का आयोजन उनके लिए बेहद ताजगी भरा रहा। ध्यान और प्राणायाम के सत्र के बाद उन्होंने खुद को बेहद ऊर्जावान महसूस किया और इसे अपनी दैनिक जीवनशैली में शामिल करने का संकल्प लिया। श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया।

कौन लेगा टीम में हार्दिक पंड्या की जगह...?

डेस्क न्यूज।

भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या खेलने की स्वीकृति मिलने के कुछ घंटे बाद बुधवार को अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज से बाहर हो गए जब उनकी जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया।

पंड्या बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी पीठ की ऐंठन की चोट से उबरने के बाद खेलने की मंजूरी लेने गए थे। यह चोट उन्हें आईपीएल में मुंबई इंडियन्स के लिए खेलते समय लगी थी। हो सकता है कि यह नई चोट सीओई में आकलन के दौरान पूरे 10 ओवर की गेंदबाजी करने की वजह से लगी हो। अब सबसे बड़ा सवाल है कि पंड्या की जगह वनडे टीम में किस खिलाड़ी को मौका मिलेगा।

शिवम दुबे-हार्दिक के अफगानिस्तान के खिलाफवनडे सीरीज में न खेलने से उनकी जगह शिवम दुबे को मौका दिया जा सकता है. शिवम भी एक ऑलराउंडर हैं और हार्दिक की अनुपस्थिति में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दुबे के पास भी भी बल्ले और गेंद से योगदान देने की क्षमता है। शिवम ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मैच अगस्त 2024 में श्रीलंका के खिलाफखेला था और वह इस फॉर्मेट में वापसी करने के लिए उत्सुक होंगे। शिवम ने अब तक भारत के लिए 4 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने बल्ले से सिर्फ43 रन बनाए हैं और गेंद से एक विकेट लिया था।

अक्षर पटेल-हार्दिक की जगह अक्षर पटेल को भी मौका मिल सकता है। अक्षर पटेल स्पिन ऑलराउंडर हैं और अपनी फिरकी से अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। अक्षर पटेल ने भारत के लिए अबतक 71 वनडे मैच खेले हैं और 75 विकेट लिए हैं।

क्या सारांश जैन की खुलेगी किस्मत!

मध्य प्रदेश के 33 साल के ऑलराउंडर सारांश जैन घरेलू क्रिकेट और भारत । के सबसे अनुभवी ऑलराउंडरों में से एक हैं। सारांश ने अब तक 47 लिस्ट-। मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 80.37 के स्ट्राइक रेट से 553 रन बनाए हैं और 38 विकेट भी लिए हैं। अगर भारतीय टीम हार्दिक की जगह किसी अनुभवी खिलाड़ी को चुनना चाहती है, तो मध्य प्रदेश के इस ऑलराउंडर पर विचार किया जा सकता है।

आकिब नबी को भी मिल सकता है मौका!

जम्मू-कश्मीर के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज और ऑलराउंडर, आकिब नबी भारत की वनडे टीम में चोटिल हार्दिक पंड्या की जगह शामिल किए जाने के मजबूत दावेदारों में से एक हैं। नबी मुख्य रूप से अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और घरेलू क्रिकेट में अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से कमाल कर चुके हैं। रणजी ट्रॉफी में उनके शानदार प्रदर्शन के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इस साल विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में भी उनका परफॉर्मेंस शानदार रहा था। 29 साल के इस खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए सात मैचों में 14 विकेट लिए। इसी सीजन उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ नाबाद शतक भी लगाया था। इसके साथ ही वह 50 ओवर के मैच में नंबर 8 या उससे नीचे बैटिंग करते हुए शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय बैटर भी बने थे।

चुनाव आयोग के गेट पर आरएसएस की ड्रेस!

भोपाल।

मध्य प्रदेश की राज्यसभा चुनावी लड़ाई अब नामांकन पत्रों और कानूनी दलीलों से निकलकर सड़क, प्रतीक और सियासी संदेशों की जंग में बदल गई है। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के एक दिन बाद बुधवार को यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भोपाल स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे।

लेकिन इस बार उनके हाथों में सिर्फ झंडे और तख्तियां नहीं थीं. वे अपने साथ आरएसएस की ड्रेस भी लेकर आए थे। जब कार्यकर्ता सीईओ दफ्तर पहुंचे तो गेट बंद मिला। कुछ देर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने वही आरएसएस की ड्रेस निर्वाचन कार्यालय के गेट पर टांग दी और वहां से चले गए।

इन यूथ कांग्रेस के नेताओं का आरोप सीधा और तीखा था। पार्टी का कहना है कि संवैधानिक संस्थाएं अब निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहीं, बल्कि वैचारिक और राजनीतिक दबाव में फैसले ले रही हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन इसलिए खारिज कराया गया ताकि भाजपा मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटें बिना मुकाबले जीत सके।

यूथ कांग्रेस नेता अंकित दुबे ने इस प्रदर्शन को लेकर कहा, ष्निर्वाचन आयोग के अधिकारी भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए हमने यह ड्रेस वहां टांगी है, ताकि वे इसे खुलकर पहनकर अपना काम करें।ष

रातभर चला हाई-वोल्टेज सियासी ड्रामा

इससे पहले मंगलवार रात सीईओ कार्यालय के बाहर हाई-वोल्टेज सियासी ड्रामा देखने को मिला। रात करीब 10रू30 बजे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे और गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लेटकर विरोध किया। देर रात तक कार्यालय के बाहर नारेबाजी और प्रदर्शन चलता रहा। कांग्रेस ने बुधवार को 11 बजे निर्वाचन आयोग कार्यालय जाकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराने का ऐलान किया था। हालांकि अंतिम समय में पार्टी का तय कार्यक्रम रद्द हो गया और निर्धारित समय पर प्रतिनिधिमंडल नहीं पहुंचा। लेकिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कार्यालय पहुंच गए और उन्होंने विरोध को एक नए और आक्रामक प्रतीक में बदल दिया।

रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस का सामूहिक उपवास

कांग्रेस इस पूरे मामले को सिर्फनामांकन रद्द होने की तकनीकी कार्रवाई नहीं बता रही। पार्टी इसे संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता, लोकतांत्रिक मर्यादा और राजनीतिक संतुलन से जुड़ा बड़ा मुद्दा बना रही है।

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पूरी प्रक्रिया को इस तरह मोड़ा गया कि भाजपा के लिए राज्यसभा की राह आसान हो जाए. बुधवार को विरोध का दूसरा बड़ा मोर्चा भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर खुला, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक उपवास किया।

इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कई कांग्रेस विधायक शामिल हुए।

सांवरिया उपहार योजना के नाम पर धोखाधड़ी

इनाम में बाइक खुलने का लालच देकर रजिस्ट्रेशन के नाम अवैध वसूली

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

साइबर ठगी ओर सोशल मीडिया पर मिलने वाले लालच के झांसे में आकर लोग अनजाने में ठगी का शिकार हो रहे है। ठगी करने वाले तरह-तरह के तरीके ईजाद कर लोगो को ठगने का काम कर रहे है। रायपुरिया थाना क्षेत्र के ग्राम कुम्भाखेड़ी के एक युवक के साथ ठगी का एक मामला सामने आया है। जिसमें सोशल मीडिया पर भगवान के नाम पर उपहार योजना के कूपन बेच कर लोगों को झांसे में लिया जा रहा है। ऐसा मामला क्षेत्र के रायपुरिया थाने के अंतरगत भी सामने आया है। जिसमें ग्राम कुम्भाखेड़ी के प्रितमसिह पिता निर्भयसिंह से 3 हजार 100 रुपए की राशि ठगे जाने का मामला बताया है। वही युवक के समय से सतर्क होने से युवक बड़ी ठगी होने से बच गया। फिलहाल मामले की लिखित शिकायत रायपुरिया थाने पर दर्ज करवाई गई है।

सांवरिया उपहार योजना के नाम पर बेचे जा रहे है कूपन

श्री सांवरिया उपहार योजना के नाम से फेसबुक ओर इंस्टाग्राम पर इनामी कूपन अलग-अलग दर पर 101,199,201 की राशि लेकर बेचे जा रहे है ओर बड़ी बड़ी चार पहिया ओर दुपहिया वाहन ओर अन्य सामग्री इनाम में देने की जानकारी दी जा रही हैं। विज्ञापन देख के ग्राम कुम्भाखेड़ी के प्रितमसिह ने ऑन लाइन संपर्क कर 101 का कूपन दिनांक 29 मई को खरीदा जिसका ड्रा 30 तारीख को होना बताया। 30 मई को शाम को मोबाइल नंबर 7665805407 से व्हाट्सअप काल आया जिस पर नाम देवीलाल गुर्जर आ रहा था। उक्त व्यक्ति ने प्रीतमसिंह को इनाम में बुलेट खुलने की बात कही और व्हाट्सअप पर बुलेट बाइक के फोटो भेज कर बुलेट पसंद करने की बात कही। साथ ही इनाम में खुली बुलेट घर भेजने के लिए रजिस्ट्रेशन के 6 हजार रुपए की मांग की। प्रितमसिंह ने उक्त व्यक्ति को बातचीत कर तीन हजार पर राजी कर दो हजार उसके द्वारा भेजे गए बारकोट पर भेज दिए ओर बाकी के एक हजार भेजने की बात कही। 31मई को दुबारा उसी नंबर से व्हाट्सअप काल करके बकाया एक हजार भेजने को कहा गया ओर शाम 5 बजे तक बुलेट घर भेजने की बात कही। उक्त फर्जी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन के नाम पर प्रितमसिंह से आधारकार्ड ओर पासपोर्ट फोटो भी व्हाट्सअप पर मंगवा लिया। जिसके बाद प्रीतमसिंह ने एक हजार रुपए दूसरों से लेकर उक्त व्यक्ति को बार कोट पर भेज दिए।

शाम तक नहीं आई बुलेट, काल किया तो कहा

पुलिस ने गाड़ी पकड़ ली पांच हजार ओर भेजो

देर शाम तक जब व्यक्ति के बताए अनुसार बुलेट घर नहीं पहुंची तो युवक ने उसी नंबर पर व्हाट्सअप काल करके बुलेट बाइक घर नहीं पहुंचने की बात की तो दूसरी ओर से कहा गया कि, तुम्हारी बाइक पुलिस ने रास्ते में रोक ली है और छोड़ने के लिए 5 हजार मांग रहे है। युवक तब तक समझ चुका था कि, मेरे साथ ठगी हो चुकी है इसलिए पैसे नहीं भेजे तो दूसरी ओर से युवक को धमका कर कहा गया कि पैसे भेज कर गाड़ी छुड़ा लो वरना पुलिस तुम्हारे घर आ जाएगी और कार्रवाई करेगी। इसके बाद से योजना के नाम पर झांसा देने वाले ने फोन उठाना बंद कर दिया ओर फोन उठता तो कोई महिला बोलती है कि साहब अभी मीटिंग में हैं बाद में बात करेंगे।

रोज बदलती हैं योजना के नाम कूपन की राशि

फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले सोशल मीडिया पर इनामी कूपन की राशि की कीमत रोज बदल-बदल कर रखते है और हर दो दिन में ड्रा की तारीख देते है। इनामी लालच में आकर लोग आन लाइन कूपन खरीद लेते है और वहीं से ठगी का खेल शुरू कर देते है। इनाम खुलने के नाम पर

बकायदा कूपन धारी को ड्रॉ की सूची, खुले हुए इनाम के फर्जी फोटो भेज कर झांसे में लिया जाता है और राशि वसूली कर ठगी की जाती है। पीड़ित युवक प्रितमसिंह ने बताया कि, मैं गरीब व्यक्ति हु ओर इनाम की लालच में मैने 3101 रुपए ठगो द्वारा बताए बारकोट पर भेज दिए जो मैने दूसरों से उधार लिए लेकिन कोई इनाम नहीं मिला उल्टा पैसे अलग चले गए। मैने थाना रायपुरिया में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग कर मेरी ठगी गई राशि दिलवाने की मांग की है।

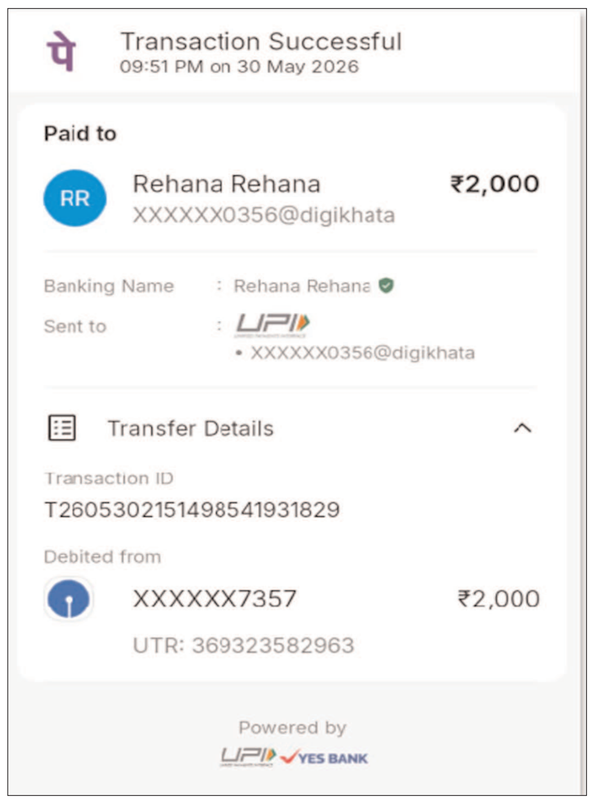

अंजान नंबरों ओर लोभ लालच से बचे

ठगी करने वाले रोज नया तरीका ला कर लोगों को फसाते है। सरकार लगातार साइबर अपराध से बचने के तरीके बता रही है। साथ ही अंजाम नंबरों से फोन या मैसेज से सतर्क रहने की आवश्यकता है। लालच ओर इनामों का झांसा देकर लोगों को खुलेआम लूटा जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इस तरीके से खुलेआम लोगों को बेवकूफबनाया जा रहा है। इस प्रकार की आईडीयों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ठगी से लोगों को बचाया जा सके।

पेट्रोल पंप से हुई डीजल चोरी का असली चोर कौन... ? पुलिस जुटी जांच में

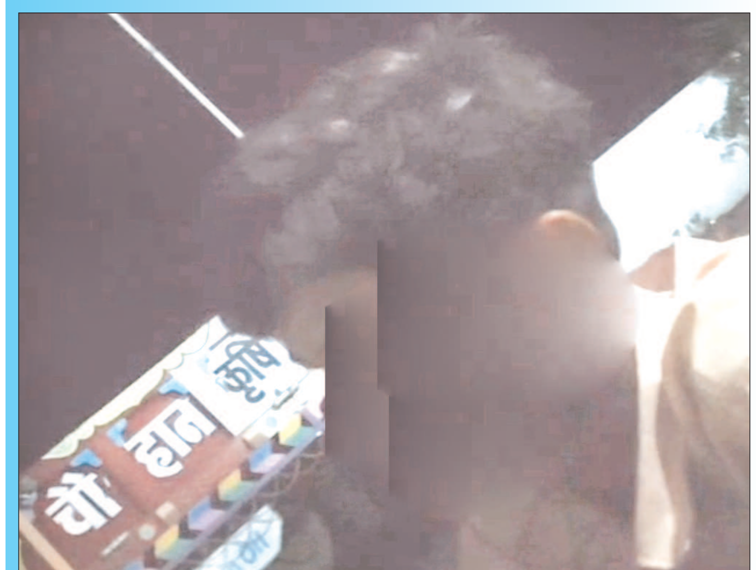

नाबालिक चालक वीडिओ के सामने बता रहा है कि, डिजल चोरी की घटना को केसे दिया अंजाम।

माही की गूंज, खवासा।

अपराध छोटा हो या बड़ा, अपराध तो अपराध ही होता है। खवासा में थांदला मार्ग स्थित इंडियन ऑयल के एक पेट्रोल पंप पर खड़ी एक बैकहोलोडर मशीन (जेसीबी) व ट्रैक्टर के साथ अन्य वाहन भी खड़े थे। लेकिन बैकहोलोडर मशीन व ट्रैक्टर के डीजल टैंक के लॉक को तोड़ व बेबी फिल्टर व पाइप काटकर दोनों में से डीजल चोरी की घटना को शातिर चोरों ने बेखोफहोकर अंजाम दिया।

उक्त घटना 2-3 जून की रात्रि की है। माही की गूंज ने पिछले अंक में उक्त चोरी होने की घटना का प्रकाशन किया था। चोरी करने वाले चोर इस तरह की घटना को अंजाम देकर समझते हैं कि, यह छोटा अपराध है और ऐसे अपराधों में न ही पुलिस अपनी रुचि दिखाती है और न ही पीड़ित द्वारा ऐसे मामले को पुलिस तक नहीं ले जाया जाता है।

इसी सोच के साथ यह शातिर अपराधी इस तरह की कई चोरियों को अंजाम देते हैं। लेकिन पेट्रोल पंप पर खड़े वाहनों में से डीजल चोरी का यह मामला बड़ा तुल पकड़ता जा रहा है। ग्राम व क्षेत्रवासी चाह रहे हैं कि, उक्त चोरी का खुलासा असली चोर को पकड़ कर पुलिस करें। उक्त चोरी के खुलासे से यह खुलासा होगा कि, गांव का ही कोई शातिर चोर है। जो इस तरह की चोरिया को अंजाम देता है। और खुलासा होने के बाद गांव में होने वाली छोटी-बड़ी चोरियों पर लगाम भी लगेगी।

कलेक्टर के आदेश के बावजूद पेट्रोल पंप पर लगाए गए कैमरे बंद मिले। लेकिन पुलिस भी तूल पकड़ते जा रहे हैं इस डीजल चोरी के खुलासे के प्रयास कर जांच में जुटी हुई है। और शंका के आधार पर कुछ लोगों को पुलिस चौकी पर भी लाया गया है। वहीं माही की गूंज की पड़ताल में भी सामने आ रहा है कि, 2-3 जून की रात्रि में 12 से 15 ट्रैक्टरों से रात भर मोरम ढोया गया। तथा उक्त मोरम का खनन थांदला मार्ग स्थित फॉरेस्ट तालाब से किया गया।

वहीं करिब 3 से 4 बजे के बिच रात्रि में बचपन स्कूल के समीप डीजल खत्म होने के कारण ट्रैक्टर बंद हो गया। वहीं दोनो पेट्रोल पंप पर भी डीजल खत्म होने के चलते इस डीजल चोरी को अंजाम दिया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है।

उक्त रात में चले एक अन्य ट्रैक्टर के नाबालिक चालक ने वीडियो कैमरे के सामने स्वीकार किया कि, रात में ट्रैक्टर में डीजल खत्म होने के बाद डीजल नहीं मिलने पर डीजल चोरी को अंजाम दिया गया। लेकिन उक्त चालक का यह भी कहना है कि, उक्त डीजल चोरी को अंजाम उसने नहीं दिया। लेकिन ट्रैक्टर व मशीन में से किसने व कैसे डीजल चोरी को अंजाम दिया यह बता रहा है व पुलिस अगर इस कड़ी से जांच करें तो उक्त डीजल चोरी के साथ गांव में हुई अन्य छोटी-बड़ी चोरियों का खुलासा होने की संभावना क्षेत्रवासी जाता रहे हैं।

उक्त नाबालिक चालक के वीडियो सामने आने के बाद चालक द्वारा उक्त वीडियो में बताया कि, ट्रैक्टर में डीजल खत्म होने के बाद उक्त चालक गांव के दो मुस्लिम युवक जिनके यहां मोरम डाला जा रहा था उनके साथ अन्य ट्रैक्टर को लेकर चला गया था। उक्त वीडियो पेट्रोल पंप के संचालक दिनेश मांडोत के पास भी गया है। जिसके बाद दिनेश मांडोत के द्वारा भी कहा जा रहा है कि, उक्त वीडियो को पुलिस को देकर पूरी जांच पुलिस द्वारा की जाएगी।

माही की गूंज ने अपने पड़ताल में उक्त दो मुस्लिम युवकों से चर्चा की तो बताया कि, बड़े बाल वाला कोई पंकज नाम का युवक हम जिस

डिजल चोरी की घटना का पिछले अंक में प्रकाशित समाचार।

ट्रैक्टर के साथ आए उसमें बैठकर आया और जिस पेट्रोल पंप से वाहनों में से डीजल चोरी हुआ उस पंप के आगे उतर गया था। और हमसे भी डीजल की व्यवस्था होगी यह भी उक्त युवक ने पूछा था। परंतु हमारे पास डीजल की व्यवस्था नहीं थी तो हमने माना कर दिया था।

उक्त दोनों युवको का कहना है कि, बचपन स्कूल के पास एक ट्रैक्टर में डीजल खत्म हुआ था यह सही है। तथा बड़े बाल वाला उक्त युवक पेट्रोल पंप के आगे उतरा था यह बात हम से जो पूछेगा उनको बताने के लिये तैयार है, परंतु डीजल चोरी किसने की यह हमें नहीं पता।

मामले में यह भी सामने आ रहा है कि, उक्त डीजल चोरी के बाद ही डीजल खत्म होने के कारण बंद हुआ ट्रैक्टर में डीजल डाला गया था और ट्रैक्टर से फिर मोरम ढोया गया था।

पुलिस को पूरी सजगता के साथ जांच करें तो नाबालिक चालक एवं अन्य ट्रैक्टर चालकों के साथ दो मुस्लिम युवकों से पूछताछ के साथ पूरे मामले का खुलासा हो सकता है कि किस के टेक्टर में डिजल खत्म हुआ? आखिर क्या यही बड़े बाल वाला पंकज नाम का कोई युवक है ने ही अपने साथी के साथ डीजल चोरी को अंजाम दिया या नहीं...? साथ ही पुलिस अगर गहराई से जांच करें तो अन्य चोरी के खुलासे भी सामने आने की संभावना क्षेत्रवासियों द्वारा जताई जा रही है और पुलिस से उम्मीद की जा रही है कि, पुलिस उक्त डीजल चोरी के सही अपराधी को पकड़ने के साथ जल्द खुलासे करें।

बजट स्वीकृत होने के एक साल बाद भी कार्य नहीं हुआ शुरू

दो जिलों को जोड़ने वाला मुख्य पुल जर्जर, क्षेत्र में कई कार्यों की स्थिति यही

माही की गूंज, बरवेट/पेटलावद।

मध्य प्रदेश के दो जिले को जोड़ने वाले धार ओर झाबुआ की सीमा पर बह रही माही नदी के राजघाट पर पुल निर्माण बजट को लेकर स्वीकृत हुए एक साल हो गया। लेकिन अभी तक कार्य प्रारंभ नही हुआ। इधर विभागीय जानकारी के अनुसार निर्माण कार्य के टेंडर नही लगे है जिससे निर्माण कार्य प्रारंभ नही हो रहा है। टेंडर लगने के बाद इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इस नदी पर पुल निर्माण का निर्णय दो जिलों के बीच आवागमन को सुगम बनाने और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। क्षेत्र वासियों का मानना है कि, माही नदी पर पुल निर्माण होने से मालवा के लिए एक ओर प्रवेश द्वार खुल जायेगा। वही पेटलावद से राजोद की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जायेगी। माही किनारे रहने वाले ग्रामीणों के लिए राजोद का सफर लगभग 30 किलोमीटर तक का सफर कम हो जाएगा।

एक नजर में

- वर्तमान में पेटलावद से राजोद- 43 किलोमीटर।
- पुल निर्णाण के बाद पेटलावद से राजोद की दूरी- 32 किलोमीटर।
- पुल निर्माण की लागत- 5 करोड़ 89 लाख रुपए।
- पुल की लंबाई- 150 मीटर।
- पुल की चौड़ाई- 8.40 मीटर।
- पुल की ऊँचाई- 20 फीट लगभग।

गौरतलब है कि, क्षेत्र की दर्जनों पंचायत के ग्रामीणों ने इस नदी पर पुल निर्माण की मांग पिछले दो दशको से की जा रही थी। जिस पर केबिनेट मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने विभाग से प्राकलन बनाकर 2025 के बजट में लेकर पांच करोड़ 89 लाख रुपए मंजूर करवाया एवं प्रशासकीय स्वीकृति भी दिलवाई।

अभी सफर मुश्किल, पुल बनने पर आसान होगा सफर

माही नदी पर पुलिया निर्माण होने से निश्चित रूप से लोगों का सफर आसान, ईंधन ओर समय की बचत एवं यात्रा सुगम होगी। वर्तमान में माही नदी पर पुलिया निर्माण नही होने से आवागमन बंद है।

माही नदी किनारे रहने वाले ग्रामीण वरसिह कटारा ने बताया कि, राजोद जाने के लिए थांदला-बदनावर मांर्ग पकड़कर जाना पड़ता है। जो कि लगभग 36 किलोमीटर पड़ता है। पुल निर्माण के बाद सात किलोमीटर में पहुच जायेगे। जिससे 28 किलोमीटर की दूरी कम तय करना पड़ेगी।

विपुल लोढ़ा स्थानीय व्यापारी बरवेट ने बताया, माही नदी पर पुल निर्माण होने के बाद यात्रा का समय व दूरी कम हो जाएगी, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी। वर्तमान में पेटलावद व्हाया सारंगी, भेसौला चौपाटी होकर राजोद पहुचने के लिए लगभग 45 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। वही पुल निर्माण होने के बाद यह दूरी 32 किलोमीटर रह जाएगी। जिससे लगभग 13 किलोमीटर का सफर कम होगा। जिससे समय और ईंधन की बचत होगी। संजय परमार भाजपा नेता ने बताया कि, माही नदी पर पुलिया निर्माण का सपना पिछले तीन दशक से देख रहे थे, जो अब साकार हो जाएगा। पुल निर्माण होने से एक ओर मालवा का द्वार खुल जाएगा। दोनों जिलों के बीच व्यापार और व्यवसाय की गतिविधियां भी बढ़ेंगी। पेटलावद ब्लाक की दो दर्जन से अधिक पंचायत राजोद के लिए सीधे जुड़ जाएगी। यहा के मजदूर राजोद जाने के लिए थांदला-बदनावर मार्ग का उपयोग करते है। पुल बनने के बाद सीधे राजोद क्षेत्र में पहुच जायेगें। जिससे समय और ईंधन की बचत होगी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- संजय भटेवरा । मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई टाइटल कोड नंबर- एमपीएचआईएन-76422